वर्ष-11, अंक-3, दिसंबर-2025

मूल्यः ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

राष्ट्र प्रेरणा स्थल विचार और सेवा का प्रतीक

आस्था का ध्वज लहराया

सुख-समृद्धि का नया युग आया

दिव्य भव्य नव्य अयोध्या
धर्म ध्वजारोहण, श्रीअयोध्या धाम

"श्री रामलला मंदिर के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा और उनका दिव्य प्रताप धर्म ध्वजा के रूप में दिव्यतम-भव्यतम श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है।"

- नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

"श्री राम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्रधर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं।"

- योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

अन्दर के पेजों में...

वर्ष- 11 अंक- 3

दिसंबर - 2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

कवर स्टोरी
पेज-28

नए भारत को सुरक्षा एवं संवेदना वाली नई पुलिस चाहिए — पेज 05

योगी सरकार वर्ष 2026 में युवाओं को देगी डेढ़ लाख सरकारी नौकरियों की सौगात — पेज 09

वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम आदेश, निर्णय केंद्र करे — पेज 14

भाजपा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे — पेज 18

मानव-मन की अदृश्य दरारें दर्शाता 'धुरंधर' — पेज 52

हार्दिक पांड्या ने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा — पेज 54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

क्रिसमस के दिन नफरत का शोर भारत की खूबसूरती पर हमला

ललित कुमार
सम्पादक

दुनिया भर में भारत को विविधताओं से भरी सांस्कृतिक छवियों वाले एक ऐसे देश के रूप में देखा-जाना जाता है, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते और एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते आए हैं। मगर हाल के वर्षों में कुछ खास त्योहारों के ठीक पहले जिस तरह द्वेष का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाने लगी है, वह न केवल देश में सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि मानवीय तकाजों के भी विरुद्ध है। क्रिसमस को ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसमें आमतौर पर देश में सभी धर्मों के लोग उत्साह के साथ शामिल होते रहे हैं। विडंबना यह है कि अब कुछ असामाजिक तत्त्व क्रिसमस के मौके पर देश के ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने लगे हैं और इसका सीधा नुकसान देश की छवि को हो रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष फिर क्रिसमस के मौके पर छत्तीसगढ़ और असम सहित कुछ राज्यों में ईसाई समुदाय के प्रार्थना स्थलों और अन्य जगहों पर दक्षिणपंथी समूहों ने हमला किया और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ मचाई।

सवाल है कि वे कौन लोग हैं, जो सद्भाव के माहौल में नफरत घोलना चाहते हैं और उन्हें देश के अल्पसंख्यक या अन्य समुदायों के पर्व-त्योहार से परेशानी होने लगी है। क्या मानवीयता के मूल्यों को अपनी आस्था का सबसे अहम पक्ष मानने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य समुदाय के त्योहार से इस कदर दुश्मनी रख सकता है? सद्भाव या सौहार्द के साथ किसी धार्मिक उत्सव को मनाए जाने से किसे दिक्कत हो सकती है? केवल निराधार आरोपों का हवाला देकर किसी ऐसे त्योहार पर अराजकता फैलाने का क्या मकसद हो सकता है, जिसमें देश के सभी धर्मों के लोग या तो सहज रहते हैं या फिर उसमें शामिल होते हैं? कथित धर्म परिवर्तन के आरोप अगर लगाए भी जाते हैं, तो इस मसले पर सरकार और प्रशासन अपना काम करेंगे या कुछ अराजक और असामाजिक तत्त्वों को अपनी ओर से हिंसा करने की छूट मिल जाती है? किसी समुदाय के भीतर डर पैदा करके किस तरह से धर्म की सेवा की जा सकती है?

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी बहाने से अन्य धार्मिक समूहों के खिलाफ हिंसा करना या तोड़फोड़ मचाना वास्तव में अपने ही देश की सांस्कृतिक छवि को नकारात्मक बनाना है। अगर इस तरह की प्रवृत्तियों को तुरंत नहीं रोका गया, तो इससे आपसी सद्भाव का माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा होगी। इतना तय है कि देश के संविधान का सम्मान करने वाली सरकारें और ज्यादातर संवेदनशील लोग धर्म के नाम पर टकराव तथा तनाव पैदा करने की कोशिशों का समर्थन नहीं करते। यही वजह है कि कई जगहों पर क्रिसमस पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि किसी भी पर्व-त्योहार के मौके पर सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। विचित्र यह भी है कि क्रिसमस के मौके पर एक ओर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाई समुदाय के साथ मेलजोल, शांति और सद्भाव का संदेश दे रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्त्व तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने में लगे थे। देश में सभी धर्मों के पर्व-त्योहारों के अवसर पर सौहार्द तथा सद्भाव की जो परंपरा रही है, उसे बचाने और मजबूत करने के लिए सरकार और समाज को एक बार फिर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

विडंबना यह है कि अब कुछ असामाजिक तत्त्व क्रिसमस के मौके पर देश के ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने लगे हैं और इसका सीधा नुकसान देश की छवि को हो रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष फिर क्रिसमस के मौके पर छत्तीसगढ़ और असम सहित कुछ राज्यों में ईसाई समुदाय के प्रार्थना स्थलों और अन्य जगहों पर दक्षिणपंथी समूहों ने हमला किया और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ मचाई।

नए भारत को सुरक्षा एवं संवेदना वाली नई पुलिस चाहिए

भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक स्तंभों में पुलिस की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। वह केवल अपराधियों से मुकाबला करने वाली शक्ति नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था, नैतिकता और जनविश्वास की संरक्षक है। परंतु विडम्बना यह है कि आम जनता के मानस में पुलिस की छवि आज भी कठोरता, डर, भ्रष्टाचार और दमन से जुड़ी हुई दिखाई देती है।

संजीव कुमार

भारतीय लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था कानून-व्यवस्था की आधारभूत धुरी है, परंतु आम नागरिक के मानस में पुलिस की छवि अभी भी कठोरता, डर और दमन से जुड़ी हुई है। इसे केवल अधिकार जताने वाली शक्ति समझा गया है, संवेदनशीलता, जवाबदेही और मित्र भाव से नहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में इसी जटिलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस की छवि तभी बदलेगी जब व्यवस्था अधिक प्रोफेशनल, अधिक उत्तरदायी और अधिक मानवीय बने। विकसित भारत की दृष्टि में पुलिस का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि समाज में भरोसे को पुनर्जीवित करने का कार्य भी है। पुलिस के पास अपराध नियंत्रण, आतंकवाद-निरोध, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, चुनाव ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा जैसी असंख्य जिम्मेदारियां हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं, कार्य-भार भारी और राजनीतिक दबाव व्यापक हैं। कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट या कठोर व्यवहार ने संपूर्ण पुलिस व्यवस्था की छवि पर चोट पहुंचाई है, इसलिए जनता पुलिस के निकट आने पर भी भय का अनुभव करती है। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति बदलने की स्पष्ट आवश्यकता जताई और युवाओं में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण पर बल दिया ताकि आने वाली पीढ़ी पुलिस को मित्र और संरक्षणकर्ता के रूप में पहचाने।

भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक स्तंभों में पुलिस की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। वह केवल अपराधियों से मुकाबला करने वाली शक्ति नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था, नैतिकता और जनविश्वास की संरक्षक है। परंतु विडम्बना यह है कि आम जनता के मानस में पुलिस की छवि आज भी कठोरता, डर, भ्रष्टाचार और दमन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। समाज पुलिस को 'डंडे' और 'खाकी' के प्रतीक रूप में पहचानता है, संवेदनशीलता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से नहीं। यही कारण है कि पुलिस सुधार दशकों से विमर्श का विषय तो रहा, लेकिन कभी जनांदोलन नहीं बन सका, न चुनावी मुद्दा बना और न ही गंभीर राजनीतिक प्राथमिकता। इसलिये मोदी ने शहरी पुलिसिंग को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को फिर से सक्रिय करने, विश्वविद्यालयों को फोरेंसिक अध्ययन के लिए प्रेरित करने और नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा नागरिक सुरक्षा संहिता पर व्यापक जनजागरूकता चलाने की जरूरत रेखांकित की। उनका यह दृष्टिकोण पुलिस को प्रतिक्रियाशील संस्था से आगे बढ़ाकर बुद्धिमान, वैज्ञानिक, पूर्वानुमान आधारित और विश्वसनीय संस्था बनाने की दिशा है।

प्रधानमंत्री की दृष्टि का महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली मशीन नहीं बल्कि समाज का सहभागी तंत्र है। यदि पुलिस व्यवहार में संवेदनशीलता, संवाद, पारदर्शिता और विनम्रता विकसित करे तो जनविश्वास स्वतः बढ़ेगा। नए कानूनों के बारे में जन-जागरूकता अभियान इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब जनता उन्हें समझती और स्वीकार करती है। अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए पुलिस का प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता, इंटेलिजेंस नेटवर्क और फोरेंसिक क्षमता मजबूत होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने नेटग्रिड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकीकृत डेटाबेस के प्रभावी उपयोग पर जोर देकर पुलिसिंग को डेटा आधारित, कृत्रिम बुद्धिमता-एआई और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने की दिशा दिखाई है। उन्होंने प्रतिबंधित संगठनों की सतत निगरानी, नशीली दवाओं के विरुद्ध बहुस्तरीय रणनीति, कट्टरपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में विकास आधारित समाधान, तटीय सुरक्षा के नवाचार, तथा प्राकृतिक आपदाओं में सक्रिय पुलिस नेतृत्व की आवश्यकता भी व्यक्त की। यह सब उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें पुलिस केवल अपराध से लड़ने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि विकास की रणनीतिक सहभागी शक्ति है।

परंतु पुलिस सुधार केवल निदेशों से संभव नहीं; इसके लिए संतुलित एवं अत्याधुनिक ढांचे की जरूरत है जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन, मनोबल, आचार-नीति, राजनीतिक निर्भरताओं से मुक्ति और सामाजिक सम्मान शामिल हों। आलोचना जितनी महत्वपूर्ण है, पुलिस के संघर्षों को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इसी दोतरफा समझ से सुधार का रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि पुलिस नेतृत्व खुद को नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करे, लक्ष्य स्पष्ट करे और वह व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिक पुलिस को भय से नहीं बल्कि विश्वास से देखें।

विकसित भारत की यात्रा में सुरक्षा, न्यायबोध और अनुशासन की संरचना को सशक्त बनाने के लिए पुलिस का आधुनिक, मानवीय और विश्वसनीय स्वरूप अनिवार्य है। यह सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और चरित्र का परिवर्तन है। तभी खाकी का सम्मान लौटेगा, जनता का विश्वास मजबूत होगा और पुलिस व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में पहचानी जाएगी।

प्रधानमंत्री के ताजा विचारों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की छवि सुधारने का अर्थ केवल कठोरता घटाना नहीं, बल्कि उसे प्रोफेशनल, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है। आज

जरूरत इस बात की है कि पुलिस व्यवस्था के लिए भय का नहीं, विश्वास और सुरक्षा का केंद्र बने। शहरी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, पर्यटक पुलिस को पुनर्जीवित करने और नए आपराधिक कानूनों पर जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पुलिस 'डंडे की ताकत' से आगे बढ़कर 'मदद की शक्ति' बनेगी। यदि नागरिक को यह अनुभव होने लगे कि पुलिस मदद के लिए तत्पर है, उसके अधिकारों का सम्मान करती है और कानून का निष्पक्ष पालन करती है, तो खाकी वर्दी का अर्थ केवल अनुशासन नहीं बल्कि विश्वास, अभय और सहारा प्रतीत होगा। यही वह परिवर्तन है जो विकसित भारत की सोच में निहित है।

अंग्रेजी शासकों ने अपने शासन को थोपने, जनता को नियंत्रित करने और भय-आधारित प्रशासन चलाने हेतु पुलिस तंत्र की रचना की। 1860 के कानून के आधार पर स्थापित भारतीय पुलिस का मूल चरित्र दंडात्मक, शासक-केन्द्रित और कठोर शक्ति-प्रयोग वाला था। स्वतंत्रता के बाद भी इस व्यवस्था में सार्थक बदलाव न होना एक विडंबना है। आजाद भारत ने लोकतंत्र अपनाया पर पुलिस ढांचे ने अभी तक औपनिवेशिक सोच को पूरी तरह त्यागा नहीं। परिणामतः पुलिस जनसेवा की बजाय सत्ता को बचाने और भय पैदा करने का उपकरण बनी रह गई। आज आवश्यकता है कि भारत का पुलिस तंत्र भारत के मूल्यों के अनुरूप पुनर्निर्मित हो। विकसित भारत को विकसित सोच वाली पुलिस चाहिए जो नागरिकों के साथ विश्वास-आधारित संबंध बनाए, दमन नहीं बल्कि संरक्षण दे, और कानून को लागू करने में नैतिकता, पारदर्शिता और मानवता को प्राथमिकता दे। ऐसी पुलिस व्यवस्था ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की प्रहरी बन सकती है और भारत की सभ्यता-संस्कारों का प्रतिबिंब भी।

इसी संदर्भ में पुलिस थानों के नामकरण की सोच पर पुनर्विचार भी आवश्यक है। 'थाना' शब्द में दमन और भय की छाया रही है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में वह नागरिक सहारा का स्थान होना चाहिए। यदि उन्हें 'सुरक्षा केंद्र', 'नागरिक सहायता केंद्र', 'पुलिस सेवा भवन', 'अभय केंद्र' या 'सहयोग प्रहरी केंद्र' जैसे नाम दिए जाएं तो नागरिक के मानस में पुलिस की भूमिका का अर्थ बदलने लगेगा। नाम केवल शब्द नहीं होता, वह भाव, चरित्र और अनुभव निर्मित करता है। इस सकारात्मक नामकरण से पुलिस केन्द्र केवल शिकायत या धमकाने का प्रतीक नहीं बल्कि सहायता, समस्या-समाधान, विश्वास और न्याय का केन्द्र बन सकता है। यह प्रतीकात्मक परिवर्तन, यदि व्यवहार सुधार के साथ जुड़ जाए, तो पुलिस के प्रति जनता में सम्मान, निर्भयता और साझेदारी की भावना और अधिक मजबूत होगी और यही वह दिशा है जिसे विकसित भारत की सुरक्षा, नीतिगत सोच और संवेदनशील शासन का स्वरूप कह सकते हैं।

इसके विपरीत आज की वास्तविकता यह है कि जब पुलिस दरवाजे पर आती है, तो नागरिक घबराता है-'कहीं फंस न जाऊं।' यह भय उस विश्वासहीनता का परिणाम है जिसे बदलना आवश्यक है। अपराध की प्रकृति बदल रही है, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग नेटवर्क-इनसे मुकाबले के लिए बेहतर प्रशिक्षण, तकनीक और इंटेलिजेंस चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस सबसे प्रत्यक्ष शासन-कर्म है। जनता रोज उसे देखती, झेलती और समझती है। खराब अनुभव सीधे शासन के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। विकसित भारत 2047 की आकांक्षाओं में पुलिस वह संरचना है जो सुरक्षा, अनुशासन, न्याय और सामाजिक साझेदारी को सुनिश्चित करती है। पुलिस की वर्दी के भीतर मनुष्य, संवेदना और विवेक दिखाई दे, तभी खाकी का सम्मान लौटेगा और जनता का विश्वास सुदृढ़ होगा। नए भारत के निर्माण में पुलिस का यह रूपांतरण एक निर्णायक धुरी होगा, जहां सुरक्षा और संवेदनशीलता साथ-साथ चलें, और जहां कानून केवल भय नहीं बल्कि न्याय और विश्वास का प्रतीक बने।

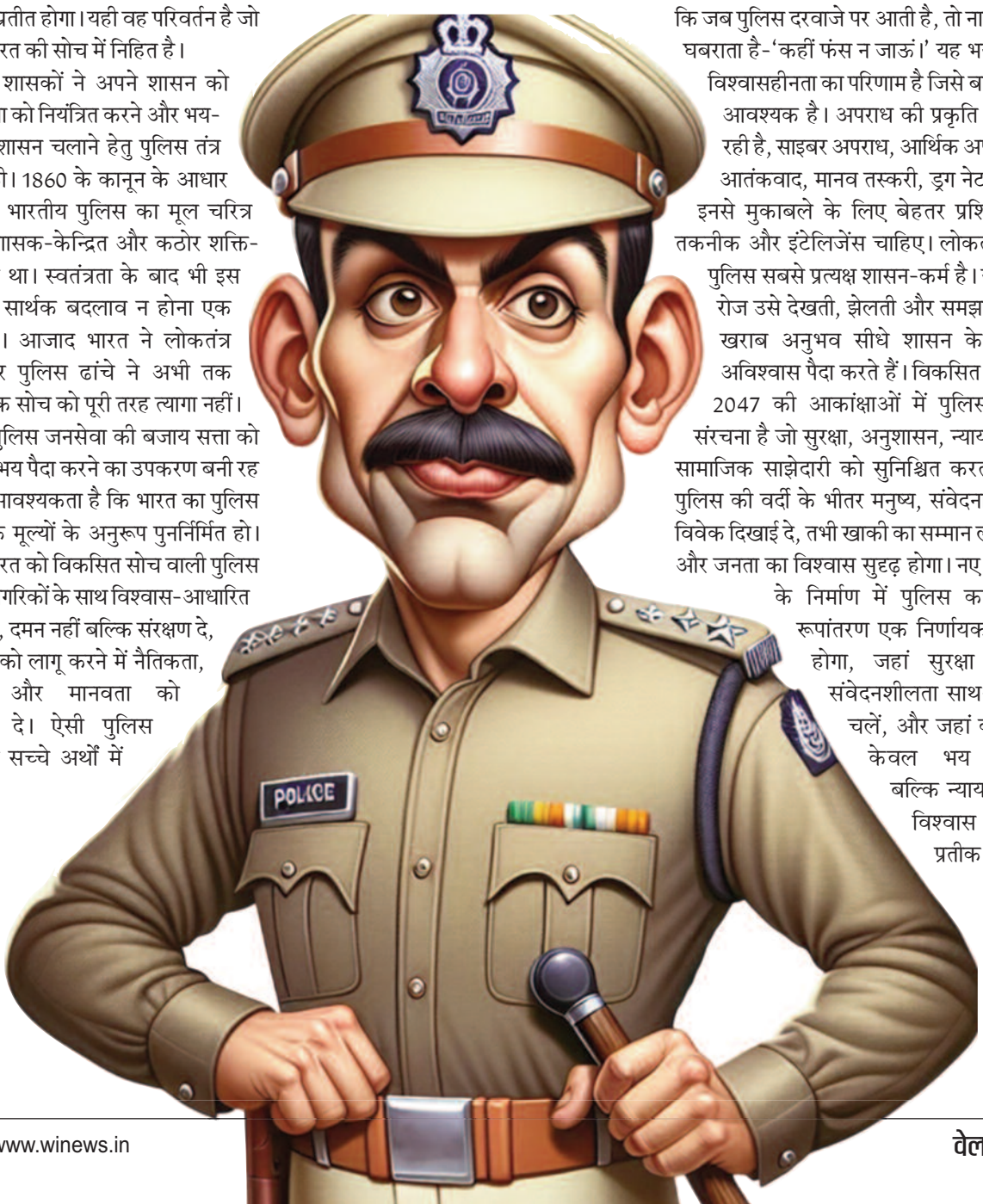

सदियों के घाव भर रहे, वेदना विराम पा रही और संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने किया श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने अपनी भावनाओं का आगाज 'सियावर रामचंद्र की जय, जय सियाराम' से किया। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत व विश्व राममय है। हर रामभक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष, असीम कृतज्ञता, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहूति है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्ज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं, आज भगवान श्रीराम मंदिर के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्रीराम का दिव्य प्रताप इस धर्मध्वजा के रूप में दिव्यतम, भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह धर्मध्वज केवल ध्वज नहीं, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज

उज्जवल रस्तौगी

है। इसका भगवा रंग इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द व अंकित कोविदार वृक्ष रामराज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। यह ध्वज संकल्प, सफलता और संघर्ष से सृजन की गाथा है। यह ध्वज सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है। यह ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणीति है। सदियों और सहस्त्राब्दियों तक यह धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों व सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। यह धर्मध्वज आ'न करेगा कि जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। धर्मध्वज उद्घोष करेगा कि सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। यह धर्मध्वज प्रेरणा बनेगा 'प्राण जाय पर वचन न जाई' अर्थात जो कहा जाए, वही किया जाए। यह धर्मध्वज संदेश देगा कि 'कर्म प्रधान विश्व रचि राखा' अर्थात विश्व में कर्म व कर्तव्य की प्रधानता हो। धर्मध्वज कामना करेगा कि भेदभाव, पीड़ा-परेशानी से मुक्ति मिले और समाज में शांति व सुख हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्मध्वज संकल्पित करेगा कि हम ऐसा समाज बनाएं, जहां गरीबी, दुख या लाचारी न हो। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। धर्म ध्वज भी मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। यह ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों-युगों तक प्रभु श्रीराम के आदेशों व प्रेरणाओं को मानव तक पहुंचाएगा। पीएम मोदी ने करोड़ों रामभक्तों के साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग देने वाले दानवीरों, श्रमवीरों, योजनाकारों, वास्तुकारों का आभार जताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या वह भूमि है, जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है, जहां से श्रीराम ने जीवनपथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे

समाज की शक्ति व संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्रीराम अयोध्या से वनवास गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मयार्दा पुरुषोत्तम बनकर आए। उनके मयार्दा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषादराज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान के समर्पण के साथ ही अनगिनत लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए समाज की सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर, मां शबरी, निषादराज गु' का भी मंदिर है। यहां एक ही स्थान पर मां अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और संत तुलसीदास हैं। रामलला के साथ-साथ इन ऋषियों के भी दर्शन यहीं होते हैं। जटायु व गिलहरी की मूर्ति भी बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह मंदिर आस्था के साथ मित्रता, कर्तव्य व सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को शक्ति देते हैं। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें मोक्ष नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी इसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, वर्ग, क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब सबके प्रयास से ही हमें विकसित भारत का निर्माण करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि आने वाले एक हजार वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। जो सिर्फ वर्तमान की सोचते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के बारे में सोचना है। जब हम नहीं थे, यह देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे, यह देश तब भी रहेगा। हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें प्रभु राम और उनके व्यक्तित्व को सीखना होगा। उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। राम यानी आदर्श, राम यानी मयार्दा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम

यानी सत्य-पराक्रम का संगम। राम यानी धर्मपथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान व विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण, राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, राम यानी विनम्रता में महाबल, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। राम सिर्फ व्यक्ति नहीं, राम मूल्य हैं, मयार्दा हैं, दिशा हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित व समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो अपने भीतर राम को जगाना होगा। अपने भीतर के राम की प्राण-प्रतिष्ठा करनी होगी। इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। 25 नवंबर का ऐतिहासिक दिन विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। पीएम ने धर्मध्वज पर अंकित कोविदार वृक्ष का जिक्र किया और कहा कि यह वृक्ष उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। उन्होंने श्रीराम जी से कहा कि सामने जो तेजस्वी प्रकाशमय विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वह अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिह्न अंकित है। आज जब राम मंदिर प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है तो यह केवल वृक्ष की ही नहीं, बल्कि यह हमारी स्मृति की भी वापसी है।

अस्मिता का पुनर्जागरण है। हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम पहचान भूलते हैं तो स्वयं को खो देते हैं, जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। इसके साथ ही गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी जरूरी है।

पीएम मोदी ने कहा कि 190 साल पहले 1835 में मैकाले नामक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आग्रह किया था कि आने वाले 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो सोचा था, उसका प्रभाव व्यापक हुआ। हमें आजादी तो मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज-व्यवस्था अच्छी है। हमारी चीजों में खोट ही खोट है। गुलामी की मानसिकता ने स्थापित किया कि हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच यह है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है।

पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीर मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का शिलालेख है, जिसमें बताया गया कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी और लोग कैसे सरकार चुनते थे। हमारे यहां तो मैग्नाकार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। गुलामी की मानसिकता के कारण भारत की पीढ़ियों को जानकारी से वंचित रखा गया। हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की मानसिकता ने

डेरा डाला हुआ था। भारतीय नौसेना के ध्वज पर सदियों तक ऐसे प्रतीक बने रहे, जिनका हमारी सभ्यता, शक्ति, विरासत से कोई संबंध नहीं था। हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया। सिर्फ डिजाइन में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि यह मानसिकता बदलने का क्षण था। यह घोषणा थी कि भारत अपनी शक्ति, प्रतीकों से परिभाषित होगा, न कि किसी और की विरासत से।

पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या में भी परिवर्तन दिख रहा है। गुलामी की मानसिकता ही है, जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में वैल्यू सिस्टम हैं। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम्के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर, हर भारतीय के मन और भारत के कण-कण में राम हैं। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। यदि हम ठान लें तो अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे, तब जाकर ऐसी ज्वाला प्रज्ज्वलित होगी और ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि रामपथ, भक्तिपथ व जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत-अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को देश की अन्य जगहों से जोड़ रही है। अयोध्यावासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर कार्य चल रहा है। जबसे प्राण-प्रतिष्ठा हुई है, तबसे आज तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। यह वो पवित्र भूमि है, जहां 45 करोड़ लोगों के चरणरज पड़े हैं। इससे अयोध्या व आसपास के लोगों की आय में वृद्धि हुई है। विकास के पैमाने में अयोध्या कभी बहुत पीछे थी, लेकिन आज यूपी के अग्रणी शहरों में एक है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, लेकिन पिछले 11 वर्ष में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वह दिन दूर नहीं, जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों व नई संभावनाओं का है। इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्रीराम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य व धैर्य उसके पहिए हैं। उसकी ध्वजा सत्य व अच्छे आचरण की है। बल, विवेक, संयम व परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया व समता है। जो रथ को सही दिशा में रखते हैं।

1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी, जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम 10 साल में ध्वस्त करके दिखा देंगे

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी, जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है। अयोध्या को संवारने का कार्य लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है, जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेतायुग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी तो 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मयार्दा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरूदंड बनकर उभर रही है। भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता व नूतनता का संगम होगा, जहां सरयू जी की अमृत धारा व विकास धारा एक साथ बहेगी। यहां अध्यात्म व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालमेल दिखेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, जिसके पहिए में चुनौतियों से टकराने का साहस और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य हो। ऐसा रथ, जिसकी ध्वजा में सत्य व सर्वोच्च आचरण हो यानी नीति-नीयत व नैतिकता से कभी समझौता कभी न हो। ऐसा रथ, जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हों यानी शक्ति, बुद्धि, अनुशासन व दूसरे के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा व समभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार न हो और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। यह पल कंधे से कंधा मिलाने, गति बढ़ाने का है। हमें वह भारत बनाना है, जो रामराज्य से प्रेरित हो। यह तभी संभव है, जब स्वयंहित से पहले देशहित होगा और राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज समेत देश-प्रदेश से आए संत व गणमान्य नागरिक आदि मौजूद रहे। संचालन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने किया।

योगी सरकार वर्ष 2026 में युवाओं को देगी डेढ़ लाख सरकारी नौकरियों की सौगात

योगी सरकार के नाम दर्ज होगा 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड

हरेन्द्र शर्मा

योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को अगले वर्ष बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से विभागवार सरकारी नौकरी के खाली पदों की डिटेल मांगी थी, ताकि खाली पदों पर नियुक्ति की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को डेढ़ लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है।

ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत प्रदेश विभिन्न विभागों में दी जाएगी। इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी। इसी के साथ 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकार्ड भी दर्ज हो जाएगा। योगी सरकार प्रदेश में पहली सरकार होगी, जिसने दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने की सौगात दी।

योगी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी है। यह सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुईं। इससे प्रदेश के युवाओं का योगी सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है। पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शी माहौल नहीं था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों के खाली पदों की जानकारी मांगी। सूत्रों की मानें तो योगी सरकार वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। इसके साथ ही राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती करेगी जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भी भर्ती करेगी।

अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया की विज्ञापन जाती करने के काम अंतिम चरण में है। कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल तक योगी सरकार पहली सरकार बन जाएगी जिसने दस साल में रिकॉर्ड दस लाख सरकारी नौकरियां दीं।

सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती की गयी है। इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर वर्ष 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसको लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30 हजार आरक्षी, 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी। वहीं, शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी। इसी तरह राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी।

मोदी-पुतिन की कूटनीति दुनिया ने देखी

इंद्रेश शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ भारत के संबंधों को 'ध्रुव तारे की तरह अटल' बताया। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने ही साझेदारी की नई बुनियाद रखी थी और उसके बाद दुनिया के कितने संकट देखे, दोनों देशों ने कितने उतार चढ़ाव देखे फिर भी दोनों के संबंध स्थिर रहे। दोनों देशों ने अपने नागरिकों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के साथ साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के नए लक्ष्य तय किए।

रूस समय की कसौटी पर आजमाया हुआ भारत का दोस्त है। उसे सही अर्थों में भारत का सदाबहार दोस्त कह सकते हैं। अनगिनत मौकों पर रूस का वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के काम आया है। 1971 की लड़ाई के समय अमेरिका के सातवें बेड़े के सामने रूस की समुद्री ताकत भारत के काम आई थी। रूस की तकनीक से भारत की सेना मजबूत और सक्षम हुई है तो रूसी तकनीक से भारत कुडनकुलम में सबसे सफल तरीके से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। रूसी तेल व गैस ने न सिर्फ भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित की। उसी रूस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की दोस्ती को एक नई ऊंचाई दी है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चार साल के बाद भारत की यात्रा पर आए तो जिस सहज अंदाज में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकातें हुईं और जितने मंचों पर दोनों ने अपनी बात रखी उससे कूटनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर दोनों की वैचारिक स्पष्टता और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की सोच सामने आई। दोनों के बीच भरोसा ऐसा दिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की गाड़ी 'बीस्ट' से चार गुना ज्यादा सुरक्षित राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी पीछे पीछे चली और वे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर प्राइवेट डिनर के लिए गए।

दोपक्षीय संबंधों को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने बिल्कुल सही कहा कि वे सिर्फ तेल और गैस की बात करने भारत नहीं आए हैं। यह बात उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश था, जो उनकी यात्रा से पहले अटकल लगा रहे थे कि रूस और भारत के बीच हजारों करोड़ रुपए के रक्षा सौदे होंगे या भारत तेल व गैस की खरीद का सौदा करेगा। यह कितनी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा में कोई रक्षा सौदे होने की खबर नहीं आई। भारत एस 400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है या एस 500 भी खरीदेगा और एसयू 57 लड़ाकू विमान भी खरीदेगा। परंतु राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में इस बारे में कोई नया समझौता नहीं हुआ।

पहले कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन अपना सामान बेचने भारत आ रहे हैं। परंतु इसका उलटा हुआ राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वे भारत से रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बढ़ाने को तैयार हैं। यानी उन्होंने भारत से आयात बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दी। रूस के साथ अगर भारत का आयात बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारत के औद्योगिक और विनिर्माण सेक्टर में तेजी आएगी। ध्यान रहे अभी तक ज्यादातर देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे में चलता है। अमेरिका एक बड़ा अपवाद है, जिससे भारत जितना सामान खरीदता है उससे दोगुने से ज्यादा बेचता है। हालांकि अब टैरिफ बढ़ने से अमेरिका को होने वाला आयात भी कम हुआ है और उसके बाद ही भारत अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए दूसरे बाजार तलाश रहा था। अब रूस का बड़ा बाजार भारत को मिलने की गारंटी हो गई है।

राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में जिन अनेक विषयों पर सहमति बनी है उसमें एक विषय अपनी मुद्रा में कारोबार करने की भी है। ध्यान रहे डॉलर की बढ़ती कीमत के कारण भारत का आयात बिल बढ़ रहा है। डॉलर के लिए भारत को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। रूस के साथ रुपए में कारोबार होने से भारत के आयात बिल में बड़ा अंतर आएगा, जिससे व्यापार घाटा कम होगा। ऐसे ही दुनिया के अनेक पश्चिमी देश और पूर्व में भी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भारतीयों के प्रति घृणा अपराध में बढ़ोतरी हुई है और इन देशों ने वीजा के नियम भी सख्त किए हैं ताकि भारतीय छात्रों और पेशेवरों को आने से रोका जा सके।

रूस के साथ समझौते के बाद भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए रूस में नए अवसर बनेंगे। भारत और रूस के बीच हुए 23वें सालाना शिखर सम्मेलन में इस पर सहमति बनी है कि रूस में भारत के कुशल पेशेवरों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए भारत और रूस के बीच स्किल्ड लेबर मोबिलिटी की संधि हुई है। इसी तरह से रूस भारतीय छात्रों के लिए भी अपने नियमों में ढील देगा। भारत भी रूस के नागरिकों को 30 दिन का मुफ्त वीजा देगा। यह

भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के काम आने वाला निर्णय है।

पीएम मोदी ने रूस के साथ भारत के संबंधों को 'ध्रुव तारे की तरह अटल' बताया। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने ही साझेदारी की नई बुनियाद रखी थी और उसके बाद दुनिया के कितने संकट देखे, दोनों देशों ने कितने उतार चढ़ाव देखे फिर भी दोनों के संबंध स्थिर रहे। दोनों देशों ने अपने नागरिकों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के साथ साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के नए लक्ष्य तय किए। दोनों देशों के बीच दोपक्षीय कारोबार को 2030 तक एक सौ अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभी 64 अरब डॉलर सालाना पर है। लेकिन इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लक्ष्य भले 2030 का है लेकिन इसे पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। यानी दोनों देशों के बीच कारोबार अगले एक दो साल में ही एक सौ अरब डॉलर की सीमा पार कर जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान हुए समझौतों की इसमें बड़ी भूमिका होगी। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। इसमें साझा तौर पर जलपोतों के निर्माण से लेकर शिपिंग लेन में निवेश और परमाणु ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों देशों के बीच खाद उत्पादन को लेकर करार हुआ तो मीडिया के क्षेत्र में भी पांच करार हुए। भारत में रूसी चैनल आरटी को राष्ट्रपति पुतिन ने लॉन्च किया। रूस के नेतृत्व वाले यूरेशिया इकोनॉमिक फोरम के साथ भारत की व्यापार संधि पर भी सहमति बनी है। इससे भारत के लिए एक बड़ा बाजार खुल सकता है। गौरतलब है कि भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों के लिए तेल के आयात पर निर्भर है। लेकिन इस निर्भरता को कम करने और भारत के नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में रूस बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत आते ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में रूस पूरी मदद करेगा। ध्यान रहे यह ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से बना है। इसके दो रिएक्टर काम करने लगे हैं, जबकि चार रिएक्टरों पर काम चल रहा है। तीसरे रिएक्टर के लिए रूसी ईंधन की आपूर्ति शुरू हो गई है और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जल्दी ही सारे रिएक्टर शुरू होंगे। अगर सारे रिएक्टर शुरू हो जाते हैं तो तमिलनाडु के साथ साथ पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने का भी वादा किया।

समस्त व्यापार समझौतों और राष्ट्रपति पुतिन के सद्भाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर भी बात की और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता बताई। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है। यह मामूली बात नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। जो बात राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहने से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हिचक रहे हैं वह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने बताया कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है।

निश्चित रूप से यह भारत की कूटनीति और वैश्विक आर्थिक नीति का नया दौर है। टैरिफ के जरिए भारत को वैश्विक स्तर पर कॉर्नर करने का प्रयास हुआ तो भारत ने नए रास्ते बनाए हैं। व्यापार के लिए नए बाजार तलाशे हैं तो अपनी ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने के भी नए उपाय खोजे हैं। नए दौर की कूटनीति में भारत ने दिखाया है कि अपने सारे हित किसी एक देश या किसी एक संगठन के साथ नहीं जोड़े जा सकते हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों, नागरिकों की आवश्यकताओं और ऊर्जा जरुरतों के लिए अलग अलग संधियां कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत ने रूस के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है तो यह किसी दूसरे देश के खिलाफ है। हर देश के साथ भारत के संबंध एक दूसरे के साझा हितों की वजह से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और चीन उनके दो सबसे करीबी दोस्त देश हैं। उनके दृष्टिकोण से यह बात सही होगी लेकिन चीन के साथ भारत के संबंध इससे तय नहीं होंगे, बल्कि चीन के साथ भारत के संबंध अपने हितों के आधार पर तय होंगे। इसी तरह अगर यूरोपीय संघ या अमेरिका के साथ रूस के संबंध अच्छे नहीं हैं तो उससे भारत का संबंध तय नहीं होगा। भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार संधि की है और यूरोपीय संघ के साथ भी वार्ता चल रही है।

अमेरिका के साथ भी जल्दी ही भारत की व्यापार संधि होगी। इस तरह नए भारत ने दिखाया है कि वह अब किसी एक देश या एक संगठन के भरोसे नहीं है, बल्कि एक महाशक्ति की तरह अपनी नीतियां खुद तय करने में सक्षम है। भारत उसी तरह से अपनी वैश्विक आर्थिक नीति और भू राजनीति से जुड़ी नीतियां तय कर रहा है, जैसे अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां करती हैं। भारत अपने दोस्त चुन रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर उनके साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है।

बॉन्डी बीच हमला और एक बहादुर इंसान

अहमद की यह वीरता इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था और अहमद खुद एक मुस्लिम हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह घृणा और हिंसा की विचारधारा है, जो किसी भी समुदाय को निशाना बना सकती है, लेकिन साहस और मानवता की भावना हर धर्म और समुदाय में मौजूद है।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुआ आतंकी हमला पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 14 दिसंबर 2025 को हनुक्का उत्सव के दौरान यह दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब दो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। आतंकवादी साजिद अक्रम और उनके बेटे नवेद अक्रम थे, जो इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित थे। यह हमला न केवल यहूदियों पर लक्षित था, बल्कि मानवता पर एक बड़ा आघात था। ऐसे में जब चारों तरफ अफरा-तफरी और डर का माहौल था, एक साधारण इंसान ने जो साहस

चरण सिंह

दिखाया, वह न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि संकट की घड़ी में आम आदमी भी असाधारण बहादुरी दिखा सकता है।

एक साधारण नागरिक, अहमद अल-अहमद ने जो साहस दिखाया, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जब चारों तरफ लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे, उस वक्त अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक हमलावर की ओर दौड़ लगाई, उससे बंदूक छीनी और उसे निरस्त्र कर दिया। इस संघर्ष में अहमद खुद घायल हो गए, लेकिन उनकी इस बहादुरी से अनगिनत जानें बच गईं। वीडियो फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे एक आम इंसान ने मौत को आँखों में झाँककर आतंकवादी का मुकाबला किया।

अहमद अल-अहमद कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं हैं और न ही कोई पुलिस अधिकारी हैं। 43 वर्षीय अहमद एक सीरिया मूल के मुस्लिम हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में फल बेचने का साधारण काम करते हैं। लेकिन, जब संकट आया तो उन्होंने सोचा नहीं, बस आगे बढ़ गए। यह वीरता हमें याद दिलाती है

कि साहस दिल में होता है, पद या हथियार में नहीं। आज की दुनिया में जहां आतंकवाद जैसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे उदाहरण दुर्लभ लेकिन बेहद जरूरी हैं। अहमद की यह बहादुरी न केवल बॉन्डी बीच के पीड़ितों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गई है।

अहमद की यह वीरता इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था और अहमद खुद एक मुस्लिम हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह घृणा और हिंसा की विचारधारा है, जो किसी भी समुदाय को निशाना बना सकती है, लेकिन साहस और मानवता की भावना हर धर्म और समुदाय में मौजूद है। अहमद ने न केवल यहूदियों की जान बचाई, बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय को एक संदेश दिया कि सच्चा धर्म सेवा और सुरक्षा में है, न कि हिंसा में। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और पुलिस ने उन्हें 'हीरो' करार दिया है। अस्पताल में भर्ती अहमद ने कहा कि वे फिर से वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने निदोर्षों को मरते देखा और चुप नहीं रह लेटफॉर्म पर उनके लिए सहायता राशि जुटाई जा रही है।

यह सम्मान उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने साबित किया कि एक साधारण व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है।आतंकवाद आज वैश्विक समस्या है। भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस हो या अमेरिका झ कहीं न कहीं नफरत की यह आग भड़कती रहती है। ऐसे में सरकारें, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ अपना काम करती हैं, लेकिन कभी-कभी स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ती है कि आम नागरिक को ही आगे आना पड़ता है। बॉन्डी बीच की घटना हमें यही सिखाती है। अगर हम डरकर चुप रहें, भागें या नजर फेर लें, तो आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, तो पूरी स्थिति बदल सकती है। अहमद ने यही किया। उनकी वीरता ने न केवल हमलावर को रोका बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि संकट में एकजुट होकर मुकाबला करें। भारत जैसे देश में, जहाँ हम आए दिन आतंकी खतरों का सामना करते हैं, अहमद की यह कहानी विशेष रूप से प्रासंगिक है।

याद कीजिए 26/11 के मुंबई हमलों में ताज होटल के कर्मचारियों ने कैसे जान जोखिम में डालकर मेहमानों को बचाया था। यानी आम नागरिकों की बहादुरी भी कम नहीं। बॉन्डी बीच की घटना हमें बताती है कि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि परिस्थिति में लिया गया निर्णय है। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए - कि गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और आराम की जिंदगी में डूबी है। ऐसे में अहमद जैसे उदाहरण उन्हें जगाते हैं। वे दिखाते हैं कि हीरो फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में पैदा होते हैं। एक साधारण इंसान, जब फैसला लेता है कि अब बस बहुत हुआ, तो वह असाधारण बन जाता है। अहमद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विविधता में एकता ही हमारी ताकत है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक देश है, ठीक भारत की तरह। वहाँ मुस्लिम नागरिक ने यहूदी समुदाय को बचाया झ यह संदेश दुनिया भर में फैलना चाहिए कि नफरत की विचारधारा को हराने के लिए हमें सीमाओं से ऊपर उठना होगा। सरकारों को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में बंदूक कानूनों को और सख्त करने की बात हो रही है।

भारत में भी आतंकवाद विरोधी नीतियों को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन साथ ही, नागरिकों में जागरूकता और साहस का संचार भी आवश्यक है। स्कूलों में, सामुदायिक कार्यक्रमों में ऐसी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए जो लोगों को प्रेरित करें। अहमद अल-अहमद की वीरता को दुनिया भर में सम्मानित किया जाना चाहिए, जैसे कि कोई पुरस्कार या कोई स्मारक। क्योंकि ऐसे लोग समाज के असली रक्षक होते हैं।

बॉन्डी बीच हमला दर्दनाक है, लेकिन अहमद की बहादुरी इसे उम्मीद की कहानी बना देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी प्रकाश होता है, बशर्ते हम दिया जलाने की पहल करें। हर आम इंसान में एक हीरो छिपा है। जब कभी संकट आए, तो डरें नहीं, आगे बढ़ें। अहमद की तरह साहस दिखाएँ। यही हमारी जीत होगी- केवल आतंकवाद पर नहीं, बल्कि मानवता की जीत।

वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम आदेश, निर्णय केंद्र करे

ये एक जगह नही है, श्रद्धालु को इस समस्या से अधिकांश जगह रूबरू होना पड़ता है। जगह-जगह मंदिरों में इस समस्या का सामना होता है। लगभग 40 साल पहले हम कोलकत्ता गए। कालिका जी मंदिर में हम श्रद्धालुओं की लाइन में लगे थे कि हमारे एक साथी ने देखा और हमें इशारा कर अपने पास बुला लिया।

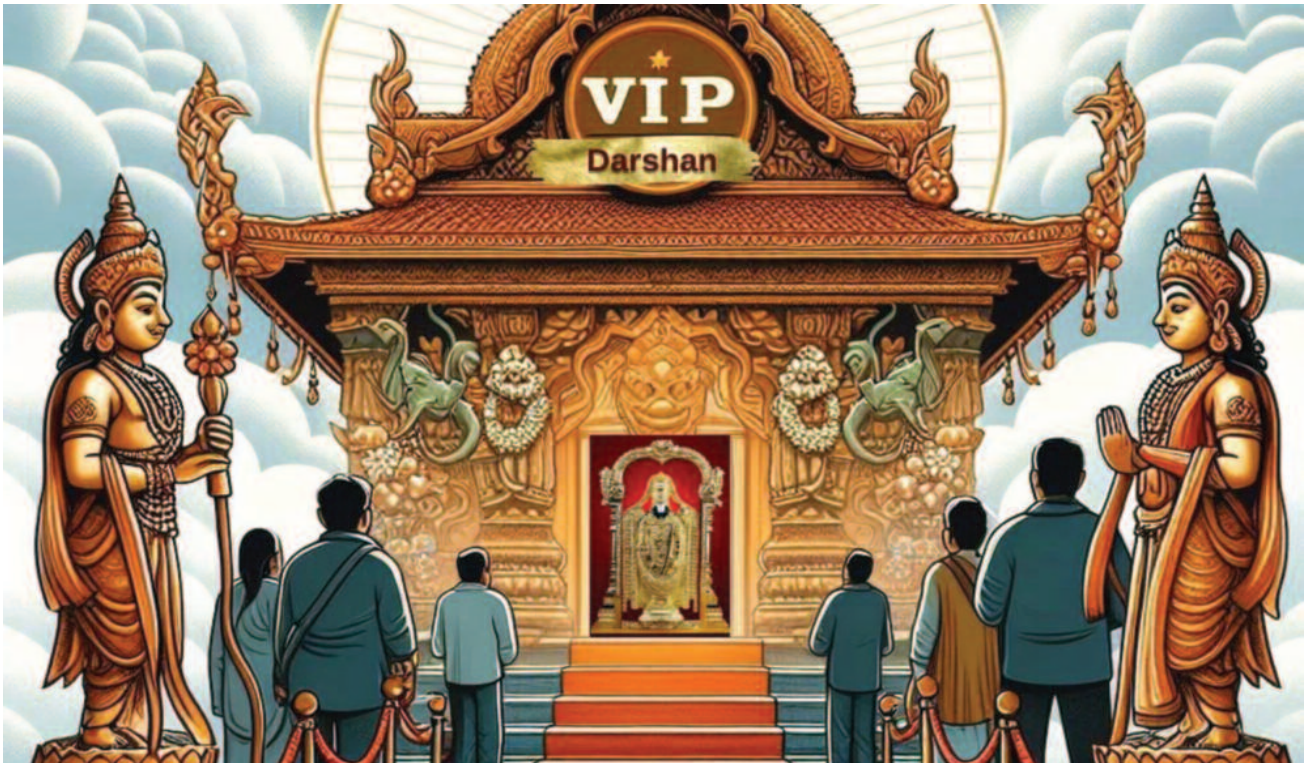

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में 'वीआईपी दर्शन' सुविधा को चुनौती देने वाली याचिका भले ही खारिज कर दी, किंतु इस याचिका पर कोर्ट द्वारा कही गई बातों की गूंज दूर तक जाएगी। यह गूंज केंद्र सरकार को विवश करेगी कि वह मंदिरों में हाने वाले वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाने वाला निर्णय लें। कोर्ट की ये गूंज आने वाले समय में मंदिरों के वीवीआईपी दर्शन कर रोक लगाने का रास्ता प्रशस्त करेगी।

ब्रिज पंवार

पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है। यह याचिका मंदिरों की तरफ से वसूले जाने वाले वीआईपी दर्शन शुल्क को समाप्त करने की मांग कर रही थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, 'हालांकि हमारी राय है कि मंदिरों में प्रवेश के संबंध में कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का उपयुक्त मामला है।' यह आदेश में दर्ज किया गया लेकिन मामला सरकार के विचार के लिए छोड़ दिया गया। पूर्व उखक खन्ना ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था का प्रतीत होता है और याचिका इस पहलू पर होनी चाहिए थी। बेंच ने कहा, 'हम स्पष्ट करते हैं कि याचिका खारिज होने से संबंधित अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, 'आज 12

ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ये मनमाना और भेदभाव वाला है। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने भी आंध्र प्रदेश से इसकी समीक्षा करने को कहा है। चूंकि, भारत में 60 प्रतिशत पर्यटन धार्मिक है, इसलिए ये भगदड़ की प्रमुख वजह भी है।' सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका विजय किशोर गोस्वामी ने डाली थी। उन्होंने मंदिरों में अतिरिक्त शुल्क लेकर 'वीआईपी दर्शन' के चलन को आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने दलील दी कि जो लोग इस तरह का शुल्क अदा करने में असमर्थ हैं, ये उनके खिलाफ भेदभाव है। याचिका में जोर देकर कहा गया था कि कई मंदिर 400 से 500 रुपये में लोगों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था करते हैं। इससे आम श्रद्धालु और खासकर महिलाएं, स्पेशली एबल्ड लोग और सीनियर सिटिजंस को दर्शन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह मामला देश भर के मंदिरों में आम लोगों और वीआईपी के बीच भेदभाव के मुद्दे को उठाता है। वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जबकि वीआईपी आसानी से दर्शन कर लेते हैं।

ये एक जगह नही है, श्रद्धालु को इस समस्या से अधिकांश जगह रूबरू होना पड़ता है। जगहझ जगह मंदिरों में इस समस्या का सामना होता है। लगभग 40 साल पहले हम कोलकाता गए। कालिका जी मंदिर में हम श्रद्धालुओं की लाइन में लगे थे कि हमारे एक साथी ने देखा और हमें इशारा कर अपने पास बुला लिया। यहां पुजारी पांच रूपया प्रति व्यक्ति लेकर सीधे दर्शन करा रहे थे। अभी वेट द्वारिका जाना हुआ। हम परिवार के छह सदस्य थे।

एक पंडित जी ने हमसे पांच सौ रुपए लिए। अलग लाइन से हमें आराम से दर्शन कराए। भीड़-भाड़ भी बची। वैसे दर्शन में दो से तीन घंटे लगते पांच सौ रुपए में आधा घंटा में दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गए। करीब दस साल पहले हम गुजरात में अम्बा जी गए थे। दर्शन की लाइन में लगे थे कि कर्मचारियों ने यह कह कर हमके रोक दिया कि दर्शन का समय समाप्त हो गया, जबकि कुछ अन्य को लगातार प्रदेश दिया जा रहा। किसी तरह हम अन्यों वाली पंक्ति में शामिल हुए। तब दर्शन हुए। दर्शन भी बड़े आराम से हुए। काफी समय हम मंदिर में रूके, जबकि ऐसा पहले संभव नही था। इस तरह का भेदभाव हमें कई जगह देखने को मिला। उज्जैन में तो आप पंडित को पांच सौ के आसपास रुपए दीजिए। वह मंदिर के गर्भ गृह में ले जाकर पूजन अर्चन कराते हैं। जो ये रकम नही देते वे गर्भगृह के बाहर ही दूर से दर्शन कर तृप्त हो जाते हैं। ओंकारेश्वर में तो पंडित जी पूजा भी आराम से और श्रद्धालुओं की पंक्ति से अलग लेकर कराते हैं। मथुरा जी के बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम आदेश से यह व्यवस्था रूकी है, अन्यथा लगभग सभी मंदिरों की हालत ऐसी ही है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, किंतु इस वीआईपी दर्शन पर रोक वाली गेंद केंद्र सरकार के पाले में यह कह कर डाल दी। बेंच ने कहा कि बेंच इस मुद्दे से सहमत है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकती। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वीआईपी के लिए ऐसा विशेष व्यवहार मनमाना है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अब केंद्र सरकार को विवश करेगा कि मंदिरों में आम आदमी के साथ हो रहे भेदभाव को रोके और बांके बिहारी मंदिर की तरह पैसा लेकर कराए जा रहे वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म करे। व्यवस्था अयोध्या जी के श्रीराम मंदिर जैसी हो, जहां श्रद्धालु बिना भेदभाव आराम से 25-30 मिनट में दर्शन कर बाहर आ सके।

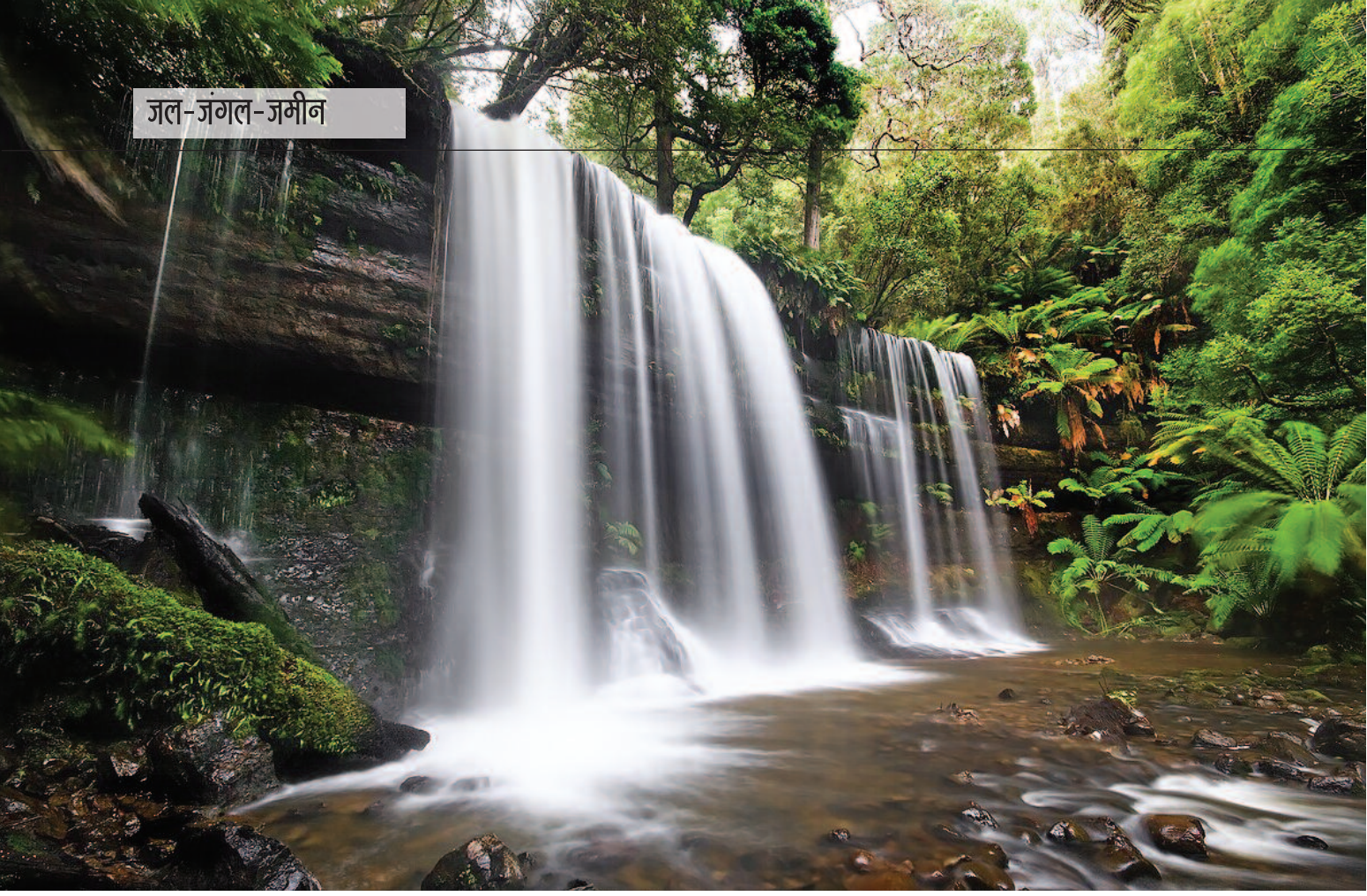

हमारे अस्तित्व की अंतिम लड़ाई

कपिल शर्मा

मनुष्य ने जब पहली बार धरती का सीना चीरकर खेती शुरू की, जब उसने बीज बोकर जीवन को सम्भालना सीखा. उसने पेड़ों की छाया और नदियों के किनारे सभ्यताएँ बसाईं. तब से लेकर आज के आधुनिक, तकनीक-प्रधान दौर तक एक सत्य कभी नहीं बदला—मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता जन्म से लेकर मृत्यु तक का अनिवार्य संबंध है, ऐसा रिश्ता जिसे न सभ्यताओं की प्रगति तोड़ सकी, न तकनीक का उन्माद, न ही पूंजीवाद की लोलुप महत्वाकांक्षा। इसीलिए आज जब हम जल-जंगल-जमीन की बात करते हैं, तो यह सिर्फ तीन शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह तीन आधारस्तंभ हैं जिन पर पूरी मानवता टिकी हुई है और जब इन स्तंभों पर खतरा आता है तो सबसे पहले टूटता है किसान, आदिवासी, मजदूर और अंततः पूरा समाज।

आज जिस तेजी से जमीनें छीनी जा रही हैं, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है और गाँवों को विस्थापित किया जा रहा है, वह सिर्फ पर्यावरणीय संकट की कहानी नहीं है—यह राजनीतिक लालच, पूंजी का दबदबा, और गरीबों की पुकार को अनसुना कर देने वाली नीति-व्यवस्था की वह भयावह कथा है जो मानव सभ्यता को एक ऐसे मोड़ पर पहुँचा रही है जहाँ से वापसी कठिन होती जा रही है। जिस प्रकार आपने कहा कि 'जमीन किसान की माँ होती है,' यह सिर्फ एक रूपक नहीं, बल्कि वास्तविकता है। जमीन खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसका जीवन इसी पर निर्भर हो, और जिसका भविष्य इसी से जुड़ा हो। जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, किसान की पहचान है, उसकी आजीविका है, उसका परिवार है, उसकी पीढ़ियों की सुरक्षा है। इसलिए जब कोई किसान जमीन खो देता है, तो वह सचमुच अनाथ हो जाता है—भूख, बेघरपन, असुरक्षा और शोषण का शिकार हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ के बिना असहाय हो जाता है। वास्तव में यह पूरा संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। यह वर्षों से चली आ रही नीतिगत विफलताओं, राजनीतिक व्यापार, निजी कंपनियों को खुली छूट, और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। आज जल-जंगल-जमीन पर जो आक्रमण हो रहा है, वह व्यवस्थित, योजनाबद्ध और गहरे आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। बड़े-बड़े प्रोजेक्टों, खनन कंपनियों, हाईवे विस्तार, स्मार्ट सिटी योजनाओं और औद्योगिक गलियारों के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीनें छीनी गईं। कहने को इसे विकास कहा गया, पर असल में यह विकास की आड़ में विनाश की प्रक्रिया थी। यह विडंबना ही है कि जिसे विकास कहा गया, उसमें सबसे अधिक 'अविकसित' वही हुआ जिसके बलिदान पर ये योजनाएँ खड़ी हुईं—किसान, आदिवासी और

बुनियादी जीविका पर निर्भर समाज।

कोरोना काल के दौरान जब पूरा देश ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहा था, जब लोग अस्पतालों के बाहर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तब पहली बार आधुनिक मनुष्य ने समझा कि प्रकृति का मूल्य कोई आर्थिक गणना नहीं है। जिस जंगल को हम कटवा देते हैं, वह जंगल भविष्य की ऑक्सीजन लेकर खड़ा रहता है। जिन पेड़ों को हम मुनाफे की आंख से देखते हैं, वही पेड़ हमारी साँसों में प्राण भरते हैं। कोरोना काल ने हमें यह सिखाया कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता–पर्यावरण, जीवन और स्वास्थ्य, पैसा देकर वापस नहीं मिलता। ऑक्सीजन की एक साँस का मूल्य तब समझ में आया, जब पैसेवाले से लेकर साधारण आदमी तक हर कोई एक सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा था। यह वह दौर था जिसने दुनिया को चेताया कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, और उनका संरक्षण हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चेतावनियाँ बहुत जल्दी भुला दी जाती हैं। कोरोना की त्रासदी बीते अभी दो-तीन साल ही हुए होंगे पर सरकारें फिर वही गलतियाँ दोहरा रही हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं, खनन कंपनियों को खुले पट्टे दिए जा रहे हैं, और जमीनों का अधिग्रहण तेजी से बढ़ रहा है। आदिवासी समुदाय जो सदियों से जंगलों के रक्षक रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। कई जगहों पर वे गोली खाकर भी जंगल की रक्षा करते दिखते हैं। मध्यप्रदेश से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ तक, ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जहाँ आदिवासी अपनी जान देकर भी पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हुए दिखे। लेकिन यह सवाल उठना जरूरी है कि आदिवासी ही क्यों लड़ें? यह लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, न सिर्फ किसानों की, न सिर्फ पर्यावरणविदों की–यह लड़ाई पूरे समाज की है, पूरी मानवता की है। यह समझने की जरूरत है कि जब जंगल कटेंगे तो सिर्फ आदिवासी नहीं मरेंगे, आम आदमी भी मरेगा क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होगी। जब नदियाँ सूखेंगी तो सिर्फ गाँव नहीं प्यासे होंगे, शहर भी प्यासे होंगे। जब जमीन खत्म होगी तो सिर्फ किसान भूख से नहीं मरेगा, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, वही देश का पेट भरता है।

आज के दौर में पूंजीपतियों और सरकारों की सांठगांठ ने जल-जंगल-जमीन को सुरक्षित संसाधन नहीं, बल्कि मुनाफे का साधन बना दिया है। खनन कंपनियों के लिए जंगल सिर्फ कोयला और खनिज निकालने का क्षेत्र है। रियल एस्टेट के लिए जमीन सिर्फ कमाई का जरिया है। बड़ी फैक्ट्रियों के लिए नदियाँ सिर्फ बहता हुआ कचरा डालने का माध्यम बन गई हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों को बाजार की भाषा में तोला जाएगा, तो उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता कैसे आएगी? यही कारण है कि आज जल, जंगल और जमीन को बचाना दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक युद्ध बन गया है–और यह युद्ध बंदूक और बम का नहीं, बल्कि विचार, चेतना, समाज और राजनीति का युद्ध है।

इस पूरे संकट का सबसे दुखद पक्ष यह है कि राजनीति ने भी इस मुद्दे को कभी ईमानदारी से नहीं उठाया। चुनाव आते हैं तो जल-जंगल-जमीन पर भाषण दिए जाते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद इस विषय पर कोई नीति नहीं बनती। पर्यावरण सुरक्षा की बातें सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंचों तक सीमित रहती हैं। जमीन अधिग्रहण कानूनों में संशोधन कर उन्हें और कंपनियों के पक्ष में बना दिया जाता है। आदिवासियों के वन अधिकार कानून को लागू करने में सरकारें जानबूझकर ढिलाई बरतती हैं ताकि कंपनियों को जमीन मिलने में आसानी हो। किसान आंदोलन हों या वनाधिकार आंदोलन–सरकार का रवैया ज्यादातर कठोर रहता है, जैसे किसान और पर्यावरण कार्यकर्ता विकास के दुश्मन हों। लेकिन सच्चाई यह है कि जल-जंगल-जमीन को बचाना विकास का विरोध नहीं, बल्कि असली विकास की रक्षा है क्योंकि सच्चा विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण दे सके। आज अगर हम जंगल काटकर, नदियाँ सुखाकर, और किसानों को उजाड़कर हाईवे और फैक्ट्री खड़ी कर देंगे तो कल की पीढ़ी इन फैक्ट्रियों में काम करने वाली मजदूर नहीं होगी–यह फैक्ट्रियाँ ही डूब जाएँगी क्योंकि पानी नहीं बचेगा, खेती नहीं बचेगी, जलवायु अनियंत्रित हो जाएगी।

इसीलिए यह जागरण बहुत जरूरी है कि हम जल-जंगल-जमीन की लड़ाई को किसी एक समुदाय, एक राज्य, या एक वर्ग की लड़ाई न समझें बल्कि इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मानें। किसान, आदिवासी, मजदूर, पर्यावरणविद, विद्यार्थी, महिलाएँ और शहरों के पढ़े-लिखे लोग–सब इस लड़ाई के हिस्सेदार हैं क्योंकि यह पृथ्वी किसी कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यह 7 अरब लोगों का साझा घर है।

आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने स्तर से भी इन संसाधनों की रक्षा करें। एक पेड़ लगाना छोटा काम लगेगा, पर यही छोटे कदम बड़े परिणामों की नींव रखते हैं। अनावश्यक पेड़ कटाई रोकना, पानी का संरक्षण करना, अपनी जमीन पर जैविक खेती को बढ़ावा देना, और पर्यावरण-विनाशकारी परियोजनाओं के खिलाफ आवाज उठाना–ये सब हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

और सबसे अधिक जरूरत है राजनीतिक दबाव बनाने की–क्योंकि जब तक जनता संगठित होकर सरकारों से जवाब नहीं मांगेगी, तब तक पूंजीवादी कंपनियों के सामने झुकी हुई नीतियाँ बदलने वाली नहीं हैं। आज अगर जल-जंगल-जमीन को बचाना है तो राजनीति को बदलना होगा। ऐसी राजनीति लानी होगी जो विकास के नाम पर विनाश की परियोजनाएँ न बेचे, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षा की गारंटी दे। नोटों की गड्डियाँ ऑक्सीजन नहीं दे

भाजपा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे

देखा जाए तो भाजपा आलाकमान का यह कदम बिहार में भाजपा की मजबूती को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है, जहां नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं जो पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक है। वहीं, बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्हें दिल्ली में आधिकारिक आवास और केंद्रीय मंत्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

प्रवीण सिंह कुशवाहा

समकालीन भाजपा के कुशल सियासी शिल्पी समझे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का चाणक्य करार दिए जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की युगल प्रभावशाली जोड़ी ने 14 दिसंबर को यकायक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तीसरी पीढ़ी के कद्दावर और सूझबूझ वाले युवा नेता नितिन नबीन के नाम की घोषणा करवाकर न केवल सबको चौंकाया है, बल्कि एक तीर से कई सियासी निशाने भी साधे हैं। इसके सियासी मायने भी दूरगामी और दिलचस्प साबित होंगे, क्योंकि मोदी-शाह के सियासी तरकश से निकले इस प्रभावी तीर ने आरएसएस-भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी आश्चर्य चकित कर दिया है।

बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सत्तारूढ़ राजग के नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को गत दिनोंतत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी पशोपेश में पड़कर चौंक गए हैं और इस अप्रत्याशित निर्णय को सराहा, क्योंकि यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल की समाप्ति और उनको मिले बार-बार कार्य विस्तार की अवधि के दौरान आई है, जो नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव तक संगठन की कमान संभालेंगे। हालांकि, इस बात की सुगबुगाहट लंबे अरसे से जारी थी और बड़े-बड़े नाम इस होड़ में शामिल थे। इसलिए नितिन नबीन की नियुक्ति से मोदी-शाह का सियासी पलड़ा पुनः भारी प्रतीत हुआ है।

जहां तक इस नियुक्ति के कारण की बात है तो पार्टी ने नितिन नबीन के संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़, प्रशासनिक क्षमता और सिक्किम/छत्तीसगढ़ में प्रभारी/सह-प्रभारी के रूप में उनकी उल्लेखनीय सफलता को आधार बनाया है। बताया जाता है कि पांच बार विधायक और तीन बार मंत्री रह चुके नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, पटना पश्चिम इलाके से हैं तथा बूथ स्तर प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि उनकी इस नई नियुक्ति का बिहार सहित पूर्वी भारत की सियासत पर भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

देखा जाए तो भाजपा आलाकमान का यह कदम बिहार में भाजपा की मजबूती को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है, जहां नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं जो पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक है। वहीं, बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्हें दिल्ली में आधिकारिक आवास और केंद्रीय मंत्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल पार्टी उनके मनोनयन की राष्ट्रीय रणनीति से सुपरिचित है जोकि जेनरेशन नेक्स्ट को बढ़ावा देती है तथा बंगाल चुनाव जैसी चुनौतियों के लिए समय रहते ही तैयार करती है। यह पीएम मोदी और एचएम अमित शाह की प्रभावशाली सियासी दिशा में एक नई निरंतरता का संकेत है, जिसमें युवा नेतृत्व से नई ऊर्जा की उम्मीद है।

पार्टी मामलों के जानकार बताते हैं कि नितिन नबीन की नई नियुक्ति बिहार की राजनीति में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और कायस्थ वोट बैंक को मजबूत करने का संकेत देती है। यह कदम बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व दिलाता है, जहां नबीन की जमीनी पकड़ और बांकीपुर सीट पर लगातार जीत भाजपा के लिए मॉडल बनी हुई है। जहां तक भाजपा की मजबूती की बात है तो इस नियुक्ति से बिहार में भाजपा का कैडर प्रबंधन और चुनावी रणनीति तेज होगी, खासकर नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहते हुए। यही नहीं, भारत का सर्वाधिक प्रबुद्ध और प्रशासनिक प्रभाव रखने वाला कायस्थ समुदाय, जो भाजपा का कोर वोटर है, इससे प्रेरित होगा तथा पार्टी का शहरी आधार पटना जैसे इलाकों में और सशक्त बनेगा।

जहां तक एनडीए पर प्रभाव की बात है तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भाजपा की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि नबीन का राष्ट्रीय पद बिहार में केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी बढ़ाएगा। साथ ही युवा नेतृत्व का उदाहरण स्थापित कर अन्य दलों को चुनौती मिलेगी, विशेषकर आगामी विधानसभा चुनावों में। वहीं, संभावित चुनौतियां यह हैं कि मंत्री पद के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी से बिहार फोकस कम न हो, यह चिंता बनी रहेगी, हालांकि उनका छत्तीसगढ़ प्रभारी वाला अनुभव आश्वासन देता है। विपक्षी दल इसे भाजपा की बिहार-केंद्रित रणनीति के रूप में देखकर जवाबी हमला बोल सकते हैं।

नितिन नबीन भाजपा की नई रणनीति में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने, संगठनात्मक मजबूती और पूर्वी भारत में विस्तार के प्रमुख स्तंभ बनेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे बूथ स्तर प्रबंधन, चुनावी तालमेल और राज्य इकाइयों के बीच समन्वय संभालेंगे। इससे पार्टी में युवा जुड़ाव बढ़ेगा। नबीन की नियुक्ति से भाजपा 2029 लोकसभा चुनावों के लिए नेक्स्ट जेन लीडरशिप तैयार करेगी, जहां युवाओं से कनेक्ट करना प्राथमिकता होगी। वहीं,, छत्तीसगढ़ प्रभारी के अनुभव से बूथ मजबूती का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा।

जहां तक चुनावी रणनीति की बात है तो 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और असम विधानसभा चुनावों में नितिन नबीन संगठन विस्तार व तालमेल प्रबंधन करेंगे, और बिहार में मिली हालिया सफलता को दोहराने का लक्ष्य रखेंगे। इससे पूर्वी भारत पर फोकस से पार्टी का क्षेत्रीय आधार सशक्त बनेगा। जहां तक संगठनात्मक भूमिका की

बात है तो जेपी नड्डा के बाद वे केंद्रीय नेतृत्व व राज्य नेताओं के बीच पुल का काम करेंगे, और पीएम मोदी की दृष्टि को जमीन पर उतारेंगे। वहीं कायस्थ (पश्चिम बंगाल में राढ़ी कायस्थ) जैसे कोर वोट बैंक को साधते हुए सामाजिक समीकरण मजबूत होंगे।

नितिन नबीन की प्रमुख प्राथमिकताएँ भाजपा के संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सक्रियता बढ़ाना और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना रहेंगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण शामिल हैं। वहीं संगठनात्मक मजबूती के लिए वे बूथ प्रबंधन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे, जैसा छत्तीसगढ़ में सफल रहा, तथा राज्य इकाइयों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कायस्थ जैसे कोर वोट बैंक को साधते हुए शहरी और प्रबुद्ध मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाना लक्ष्य होगा।

जहां तक चुनावी लक्ष्य की बात है तो 2026 के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में संगठन विस्तार और तालमेल प्रबंधन उनकी प्राथमिकता रहेगा। इस निमित्त वे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा के लिए युवा कनेक्ट पर फोकस करेंगे। इससे पूर्वी भारत में भाजपा का आधार सशक्त बनाने से पार्टी की रणनीति को एक नई दिशा मिलेगी। उनकी नेतृत्व शैली संतुलित समझी जाती है। भाजपा को आज इसी शैली की दरकार है। लिहाजा नितिन नबीन नई जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने का संकल्प ले चुके हैं, जिसमें सशक्त नेतृत्व और कार्यकताओं से गहरा जुड़ाव प्रमुख होगा। उनका शांत स्वभाव और जमीन पर काम की छवि इन लक्ष्यों को साकार करने में सहायक बनेगी।

यहाँ भाजपा द्वारा नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का कारण सरल और स्पष्ट है, वह यह कि उनकी नियुक्ति पार्टी की नयी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और नेतृत्व में बदलाव के इर्द-गिर्द केंद्रित है। सवाल है कि आखिर नितिन नबीन को ही यह अहम पद क्यों मिला? तो जवाब होगा कि भाजपा को युवा और सक्रिय नेतृत्व देने के लिए पार्टी ने यह फैसला लिया। दरअसल भाजपा नेतृत्व चाहता है कि पार्टी में युवा, गतिशील और मेहनती नेतृत्व को मौका मिले। अभी नितिन नबीन महज 45 वर्ष के हैं और उन्हें एक युवा, ऊजार्वान तथा कर्मठ नेता के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उनका संगठनात्मक अनुभव एवं जमीनी पकड़ मजबूत है क्योंकि वे एक अनुभवी संगठनकर्ता हैं, इतनी कम उम्र में पाँच बार विधायक, मंत्री और संगठन से जुड़े रहे हैं। इस अनुभव के कारण उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, पार्टी में नई ऊर्जा और संतुलन लाने के लिए भी नेतृत्व का यह बदलाव किया गया है। इससे पार्टी में नई ऊर्जा, संतुलन और रणनीतिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। खासकर जब अगले चुनावों से पहले संगठन को मजबूत बनाना है तो नितिन नबीन को लाकर पार्टी ने अपने मकसद को स्पष्ट कर दिया है।

निःसन्देह नितिन नबीन को मिली इस नई जिम्मेदारी से बिहार और पूर्वी भारत पर भाजपा की

पैठ मजबूत होगी।ऐसा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उनकी नियुक्ति इस बात का संकेत भी है कि भाजपा पूर्वी भारत (विशेषकर बिहार-पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड व सात बहन पूर्वोत्तर राज्यों) में अपनी पैठ और नेतृत्व को सशक्त करना चाहती है। इसलिए आगामी नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी को उसने तेज कर दिया है। पार्टी का यह अप्रत्याशित फैसला एक व्यवस्थापित व महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है- जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक संगठन का संचालन सुचारु रखना। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य के नेतृत्व के लिए पार्टी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने भी सधी हुई प्रतिक्रियाएँ दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नबीन को बधाई दी है और उन्होंने उन्हें कर्मठ, अनुभवी और प्रभावशाली नेता बताया है। क्योंकि उनकी इस नियुक्ति का मुख्य कारण उनके कार्य, संगठन क्षमता और ऊर्जा को माना गया। सरल शब्दों में कहें तो भाजपा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि वे युवा, अनुभवी, संगठनात्मक रूप से मजबूत और पार्टी को नई दिशा देने वाले नेता माने जाते हैं और यह नियुक्ति भाजपा की भविष्य की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा के मोदी-शाह गुट ने नितिन नबीन जैसे उभरते हुए युवा नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इस अहम पद हेतु पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय जोशी जैसे तपे-तपाए नेता की दावेदारी को हाशिए पर डाल दिया है, जबकि उनको आरएसएस का शह प्राप्त था। लेकिन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे तीसरी पीढ़ी के नेताओं को मजबूती प्रदान करने हेतु पार्टी ने यह संतुलित रणनीति अख्तियार की है, क्योंकि यह पार्टी युवा, जमीनी नेतृत्व की ओर बढ़ रही है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि जेपी नड्डा जैसे लक्की राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराधिकारी के रूप में नितिन नबीन का चयन उनकी बूथ स्तर की मजबूती, छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार बनवाने की सफलता और बिहार-बंगाल में कायस्थ वोट बैंक प्रबंधन ने उन्हें प्राथमिकता दी। कुल मिलाकर संजय जोशी के व्यापक अनुभव के बावजूद नितिन नबीन के ऊपर दांव खेलना अमित शाह का वह तुरुप का पत्ता है जिसके लिए वह मशहूर समझे जाते हैं। ऐसा करवाकर उन्होंने युवा नेतृत्व पर फोकस बढ़ाया है जो महज 45 वर्षीय भाजपा के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और जेपी नड्डा के बाद जेनरेशन नेक्स्ट के रूप में नितिन नबीन को सत्ता सौंपने का संकेत देते हैं।

ऐसा इसलिए भी कि संजय जोशी जैसे वरिष्ठ नेता के मुकाबले नबीन का शांत स्वभाव और संगठनात्मक कुशलता पार्टी में एक नई ऊर्जा लाएगी। जहां तक रणनीतिक कारण की बात है तो इससे पार्टी ने पूर्वी भारत विस्तार, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा आम चुनाव के लिए नबीन का चयन किया है, जहां उनकी प्रशासनिक पकड़ बंगाल-असम जैसे राज्यों में उपयोगी साबित होगी। इस प्रकार नितिन नबीन द्वारा संजय जोशी की जगह लेने से बिहार-केंद्रित रणनीति मजबूत हुई, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नितिन नबीन पर अधिक है।

एक प्रकार से यह पार्टी के सियासी पैटर्न में उम्दा बदलाव का भी द्योतक है, क्योंकि उनकी यह नियुक्ति भाजपा के पुराने पैटर्न से हटकर बिहार से पांचवें बड़े नेता को राष्ट्रीय मंच देती है, जो नड्डा-जोशी जैसे तपे तपाए नेता के एक लंबे कार्यकाल के बाद पार्टी शीर्ष के लिए एक नई ताजगी लाएगी। वहीं पीएम मोदी-अमित शाह की पसंद नितिन नबीन को आरएसएस समर्थित युवा चेहरा बनाती है। बताया जाता है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नितिन नबीन की नियुक्ति के पीछे उनकी ऊजार्वान छवि, संगठनात्मक क्षमता और केंद्रीय निदेर्शों पर पूर्ण आज्ञाकारिता को प्रमुख तर्क बनाया।

बताया जाता है कि पीएम मोदी ने उनकी ऊर्जा को पार्टी मजबूती का आधार बताया, जबकि अमित शाह का अटूट विश्वास उन्हें भरोसेमंद चेहरा बनाता है। चूंकि नितिन नवीन पार्टी की तीसरी पीढ़ी के सक्षम युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इस प्रकार से भाजपा ने मात्र दो दशकों में ही तीसरी पीढ़ी को अवसर देकर नितिन नबीन को चुना, जो वाजपेयी-आडवाणी के बाद मोदी-शाह के नेतृत्व को एक नई ऊर्जा देंगे और पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक भाजपा में एक नई गति लाएंगे। वाकई 45 वर्ष की उम्र में सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बनना पूर्वी

भारत रणनीति और 2026 चुनावों के लिए तैयार करने का संकेत है।

इससे पार्टी का सामाजिक आधार दृढ़ होते हुए भी संगठनात्मक संतुलन कायम करता है। एक प्रकार से कायस्थ समाज से नया नेतृत्व लाकर जहां फॉरवर्ड वोट बैंक को मजबूत करने का कार्य किया गया है, वहीं ब्राह्मण-राजपूतों के बजाए कायस्थ को महत्व देकर ओबीसी सत्ता के साथ संतुलन साधना पार्टी का मुख्य लक्ष्य रहा जो सफल प्रतीत हुआ। यह आरएसएस समर्थित भाजपा का अभिनव प्रयोग भी है, जिसके पीछे नितिन नबीन के बूथ स्तर माइक्रो मैनेजमेंट और उनकी छत्तीसगढ़ विस चुनाव वाली सफलता ने उन्हें बंगाल-असम जैसे राज्यों के आगामी चुनावों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बनाया। इससे उन पर रणनीतिक भरोसा भी बढ़ा है।

खास बात यह है कि नितिन नबीन अब स्वतंत्र शक्ति केंद्र न बनकर मोदी-शाह की रणनीति लागू करने वाले नेता बन चुके हैं, जो नड्डा की तरह ही भाजपा के विशाल संगठन को अन्य बोझ से बचाएंगे। इसलिए यह फैसला गोपनीय रूप से लिया गया, जो केंद्रीय नेतृत्व की एकतरफा पसंद भी दशार्ता है। नितिन नबीन की भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति के राजनीतिक फायदे युवा नेतृत्व को मजबूत करना, पूर्वी भारत में विस्तार और कोर वोट बैंक को सशक्त बनाना बताए गए हैं। यह कदम पार्टी को बूथ स्तर मजबूती और 2026 चुनावों के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे संगठनात्मक लाभ यह मिलेगा कि उनकी इस नियुक्ति से भाजपा का कैडर प्रबंधन तेज होगा, खासकर बंगाल-असम जैसे राज्यों में जहां नबीन का अनुभव उपयोगी साबित होगा।

वहीं कायस्थ समाज जैसे फॉरवर्ड वोट बैंक को राष्ट्रीय मंच देकर सामाजिक संतुलन साधा गया। जिसके चुनावी फायदे भी मिलेंगे। इससे 2029 लोकसभा और राज्य चुनावों में युवा कनेक्ट बढ़ेगा, और हालिया बिहार जीत मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने का अवसर मिलेगा। इससे एनडीए गठबंधनों में भाजपा की स्थिति मजबूत बनेगी, और विपक्ष को नई व मजबूत चुनौती मिलेगी। उनकी रणनीतिक बढ़त से व केंद्रीय नेतृत्व की एकतरफा पसंद से पार्टी में अनुशासन और मोदी-शाह दृष्टि की निरंतरता सुनिश्चित हुई। बिहार से पांचवें बड़े नेता का उदय राज्य को राष्ट्रीय महत्व बढ़ाएगा।

दरअसल, नितिन नबीन के नाम की घोषणा इसलिए चौंकाने वाली मानी गई क्योंकि वह न तो मीडिया की सुर्खियों में संभावित दावेदार के तौर पर

चल रहे थे और न ही भाजपा के भीतर चर्चित नामों की सूची में शीर्ष पर थे। फिर भी पार्टी नेतृत्व ने जिस तरह अचानक उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर आगे किया, उसने पूरे राजनीतिक हलके और खुद भाजपा कार्यकताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। क्योंकि उनके नाम को लेकर पहले कोई अटकल नहीं थी, घोषणा से पहले। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नाम जोरशोर से चर्चा में थे, लेकिन नितिन नबीन का नाम लगभग कहीं नहीं लिया जा रहा था।

ऐसे में अपेक्षाकृत कम चर्चित, राज्य-स्तर के नेता को सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देना पार्टी के 'सरप्राइज फैक्टर' की मिसाल बन गया। देखा जाए तो उम्र और प्रोफाइल के फैक्टर के हिसाब से नितिन नबीन अपेक्षाकृत युवा हैं और बिहार की राजनीति से आते हुए भी उन्हें अचानक राष्ट्रीय स्तर की कमान सौंप दी गई, जिससे यह 'जेनरेशन नेक्स्ट' को आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। पांच बार विधायक और तीन बार मंत्री रह चुके होने के बावजूद उन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए उनके नाम की औपचारिक घोषणा ने चौंकाने वाला प्रभाव पैदा किया।

जहां तक राजनीतिक संदर्भ और टाइमिंग की बात है तो वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो लंबे समय से कयास चल रहे थे और माना जा रहा था कि फैसला आगे टलेगा, लेकिन अचानक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की घोषणा कर दी गई। यह फैसला ऐसे समय हुआ जब पार्टी ने ठीक एक दिन पहले यूपी में भी नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया था, जिससे डबल-स्प्राइज की राजनीतिक व्याख्याएं और तेज हो गईं।

जहां तक इसके रणनीतिक संदेश की बात है तो उनका कायस्थ समाज से आना, बिहार पृष्ठभूमि और संगठनात्मक अनुभव- सिक्किम-छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रभारी/सह प्रभारी की भूमिका- को मिलाकर देखा जाए तो यह कदम पूर्वी भारत व खास सामाजिक समूहों में पार्टी के विस्तार की रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। इसलिए घोषणा चौंकाने वाली होने के साथ-साथ यह संकेत भी देती है कि शीर्ष नेतृत्व भविष्य के पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए एक नए चेहरे.को टेस्ट कर रहा है।

देखा जाए तो नितिन नबीन बिहार के पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रह चुके भाजपा नेता हैं। वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं तथा छात्र राजनीति से अपनी सियासत शुरू कर संगठन के विभिन्न पदों पर रहे। उनका राजनीतिक सफर भी शानदार है, क्योंकि 2006 में नितिन नबीन का राजनीतिक सफर उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा की विरासत से शुरू हुआ, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे। तब वह पटना पश्चिम (अब बांकीपुर) से उपचुनाव जीतकर वह विधायक बने, उसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार पांचवीं बार बांकीपुर से जीते।

इसके साथ ही वह प्रमुख संगठनात्मक पद पर भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वहीं सिक्किम प्रभारी तथा छत्तीसगढ़ सह-प्रभारी के रूप में पार्टी की चुनावी सफलताओं में योगदान दिया। जहां तक सरकारी जिम्मेदारियों की बात है तो 2021-2022 में पथ निर्माण मंत्री, 2024-2025 में नगर विकास एवं आवास तथा कानून-न्याय मंत्री रहे। वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री तथा 14 दिसंबर 2025 से भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में बांकीपुर सहित बिहार में सड़क निर्माण ढांचा को दुरुस्त किया जाना, शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस के अलावा कानून-न्याय विभागों में मंत्री रहकर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना शामिल है। उनका कायस्थ समाज से जुड़ाव है और बूथ स्तर प्रबंधन में माहिर समझे जाते हैं। अब वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेते हुए संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति संभालेंगे, क्योंकि उनकी जमीनी पकड़ और अनुशासित छवि को केंद्रीय नेतृत्व ने भी सराहा है।

बड़ी कंपनी के सामने सरकार की लाचारी

केंद्र सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के नए नियम लागू किए थे। इन नियमों को जनवरी 2024 में लाया गया था। हालांकि, इन्हें अब जाकर पूरी तरह से लागू किया गया। इनमें पायलटों और क्रू मेंबर का ड्यूटी टाइम कर दिया गया है और आराम करने का समय बढ़ा दिया है।

देश में कोई ताकतवर कंपनी कैसे कानून का दावपेच इस्तेमाल करके सरकार को उसी के बनाए कानून के जाल में उलझा कर अपना उल्लू सीधा कर सकती है, इंडिगो एयरलाइंस विवाद इसका बड़ा उदाहरण है। इस एयरलांइस ने चार दिन तक हजारों यात्रियों को बंधक जैसी हालत में रखा। इसका फायदा दूसरी विमानन कंपनियों ने उठा कर जम कर चांदी कूटी। इस पूरी हालत के दौरान केंद्र सरकार तमाशबीन रही है। सरकार हवाई यात्रियों को हैरान–परेशान और लुटते हुए देखती रही। जब पानी सिर से गुजरने लगा तक सरकार को होश आया। आखिरकार सरकार को नियमों में छूट देकर एयरलाइंस कंपनी के समक्ष बैकफुट पर आने के लिए विवश होना पड़ा। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पायलटों के लिए बनाए गए कायदे–कानून कायदों में ढील देने का निर्णय लेना

अजीत शर्मा

पड़ा। केंद्र सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के नए नियम लागू किए थे। इन नियमों को जनवरी 2024 में लाया गया था। हालांकि, इन्हें अब जाकर पूरी तरह से लागू किया गया। इनमें पायलटों और क्रू मेंबर का ड्यूटी टाइम कर दिया गया है और आराम करने का समय बढ़ा दिया है। ऐसा पायलटों की थकान कम करने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए किया गया है। एफडीटीएल के नए नियम तय करते हैं कि पायलट कितनी देर ड्यटी पर रह सकते हैं? कितने घंटे विमान उड़ा सकते हैं? रात में कितनी बार लैंडिंग कर सकते हैं? उन्हें कितना आराम मिलना चाहिए? कितनी बार नाइट ड्यूटी कर सकते हैं? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इन नियमों को पिछली साल जनवरी में पेश किया था। इन्हें पिछले साल ही 31 मई से लागू किया जाना था। मगर एयरलाइन कंपनियों ने इसके लिए समय मांगा, जिसके बाद इन्हें टाल दिया गया। इसके बाद इन नियमों को इस साल दो फेज में लागू किया गया। इन नियमों का पहला फेज इस साल जुलाई में लागू किया गया। दूसरा फेज 1 नवंबर से लागू कर दिया गया।

सवाल यह है कि जब नए नियम सभी एयरलाइन कंपनियों पर लागू होते हैं पर इसका सबसे ज्यादा असर इंडिगो पर ही क्यों दिखा? इसका जवाब है कि इंडिगो के पास पायलटों की कमी हो गई है। इंडिगो ने जानबूझ कर यह कमी की। अन्य

एयरलाइंस कंपनियों की तरह इंडिगो के पास भी नए पायलटों की भर्ती के लिए पर्याप्त समय था, किन्तु कंपनी ने भारी आर्थिक भार को टालने के लिए भर्ती नहीं की। कंपनी ने बड़ी चालाकी से सरकार को उसी के बनाए नियमों में फांस कर इनमें ढील देने के लिए विवश कर दिया। इसके लिए कंपनी ने यात्रियों को मोहरा बनाया। यह जानते हुए भी कि कंपनी के पास पायलटों की कमी है, लगातार बुकिंग जारी रखी। फिर अचानक हाथ खड़े कर दिए। हजारों यात्रियों के फंसे होने से जब देश में हाहाकार मचा तो केंद्र सरकार को नए नियमों में ढील देने के लिए झुकना पड़ा।

डीसीजीए ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए नियमों में ढील दी जा रही है। डीजीसीए ने उन नियमों में ढील दी है, जो अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश के बाद लागू किए गए थे। साथ ही अभी क्राइसिस के समय पायलटों से मदद की अपील की डीजीसीए ने अब इंडिगो से एक डिटेल्ड रोडमैप जमा करने को कहा, जिसमें उससे क्रू की भर्ती, क्रू की ट्रेनिंग का प्लान, रोस्टर रिस्ट्रक्चरिंग और सेफ्टी रिस्क असेसमेंट का प्लान मांगा गया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को हर 15 दिन में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देने को कहा है। सरकार की ओर से केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सफाई दी कि यह फैसला केवल यात्रियों के हित में लिया गया है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, मरीजों और जरूरी यात्रा करने वालों को राहत देने के लिए।

मंत्रालय ने एयरलाइनों के साथ कम से कम छह महीने तक निरंतर संवाद भी किया। पहले इस नियम के बारे में कोई समस्या नहीं थी। एअर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी अन्य एयरलाइन ने अपने संचालन को ढाल लिया। लेकिन जो हुआ वह इंडिगो की चालक दल (क्रू) के प्रबंधन की गड़बड़ी के कारण हुआ। नायडू ने कहा कि हमने सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को एफडीटीएल नियमों में कुछ छूट दी है। इंडिगो संकट के बीच सरकार द्वारा पायलटों के नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियम (एफडीटीएल) को तत्काल प्रभाव से फिलहाल स्थगित करने के फैसले की पायलट संघ ने कड़ी आलोचना की है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डीजीसीए को एक पत्र लिखते हुए कहा कि यह फैसला सुरक्षा से सीधा समझौता है। पायलटों की थकान से यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है।

एसोसिएशन के अनुसार, इंडिगो ने जानबूझकर यह संकट खड़ा किया, जिससे उसे नियमों में ढील मिल सके। इसलिए इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और एफडीटीएल के दूसरे चरण के नियमों को पूरी तरह लागू किए जाएं बिना किसी भी एयरलाइन को इसमें छूट दिए। एसोसिएशन ने इंडिगो प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि रात्रिकालीन ड्यूटी से संबंधित मानदंडों में ढील से इंडिगो को अपने परिचालन को स्थिर करने में मदद मिलेगी, लेकिन यह छूट एक खतरनाक मिसाल कायम करेगी। डीजीसीए ने 25 नवंबर की बैठक में इस बात पर सहमति जताई थी कि किसी भी ऑपरेटर को, खासकर व्यावसायिक हितों से प्रेरित, कोई छूट या बदलाव नहीं दिया जाएगा। सभी ऑपरेटरों के पास नए एफडीटीएल को लागू करने के लिए लगभग दो साल का समय था, और वह भी दो चरणों में। इस पर्याप्त समय के बावजूद इंडिगो अपना रोस्टर तैयार करने में विफल रही और इसके बजाय एयरलाइन ने 2025 की सर्दियों के लिए अपने परिचालन को बढ़ा दिया।

एसोसिएशन ने कहा कि ये घटनाएं गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं कि सार्वजनिक असुविधा के बहाने व्यावसायिक लाभ के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए एक कृत्रिम संकट पैदा किया गया था। इंडिगो को चुनिंदा छूट देकर, डीजीसीए ने अन्य सभी ऑपरेटरों के लिए अपने परिचालन, वाणिज्यिक या समय-सारिणी संबंधी कारणों का हवाला देकर एफडीटीएल नागरिक उड्डयन आवश्यकता से समान छूट की मांग करने का रास्ता खोल दिया है। यह नागरिक उड्डयन आवश्यकता के मूल सिद्धांत और उद्देश्य को ही कमजोर करता है। एसोसिएशन ने मांग की है कि डीजीसीए इंडिगो को दी गई सभी छूट तुरंत वापस ले और एयरलाइन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करे।

संघ के अनुसार, इंडिगो ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी परिचालन क्षमता का गलत आकलन किया था; फिर भी, जनता को भारी असुविधा पहुंचाने के लिए उन्हें फटकार लगाने या दंडित करने के बजाय, डीजीसीए ने उन्हें और छूट दे दी। इस कार्रवाई ने न केवल परिचालन कुप्रबंधन को बढ़ावा दिया है, बल्कि यात्रियों की जान को भी सीधे खतरे में डाल दिया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी किरकिरी के बाद केंद्र सरकार इंडिगो के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाए पूरे मामले की लीपापोती करने में लगी हुई है। होना तो यह चाहिए था कि इंडिगो प्रबंधन के खिलाफ देश में जानबूझ कर अराजकता फैलाने का मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की जाती, ताकि दूसरी कंपनियों को मुनाफे के लिए ऐसी हरकत करने की चेतावनी मिल सके।

इसके विपरीत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 10% उड़ानों में कटौती का आदेश देकर इंडिगो को बख्श दिया। नायडू ने कहा कि पिछले हफ्ते इंडिगो के क्रू रोस्टर, फ़्लाइट शेड्यूल और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कई यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। जांच और जरूरी कार्रवाई चल रही है। महज 10 प्रतिशत उड़ान में कटौती जैसा प्रतीकात्मक दंड देने की औपचारिकता से ऐसी कंपनियों के कामकाज और आर्थिक मुनाफे के लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग सकेगा। केंद्र सरकार का चाहिए कि इंडिगो के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे, जोकि देश में नजीर बन सके, ताकि फिर कोई कंपनी आम लोगों से खिलवाड़ नहीं कर सके। अन्यथा यही माना जाएगा देश कानून से नहीं कंपनियों की मनमानी से चलता है।

लौहपुरुष सरदार पटेल और एकीकृत भारत की नींव

वल्लभ भाई पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए सन् 1905 में इंग्लैंड जाना चाहते थे लेकिन पोस्टमैन ने उनका पासपोर्ट और टिकट उनके भाई विट्ठल भाई पटेल को सौंप दिए। दोनों भाइयों का शुरूआती नाम वी. जे. पटेल था, ऐसे में बड़ा होने के नाते उस समय विट्ठल भाई ने स्वयं इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया।

संजय बैंसला

राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार पटेल की निष्ठा आजादी के इतने वर्षों बाद भी पूरी तरह प्रासंगिक है। एकता की मिसाल कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में 31 अक्तूबर 1875 को जन्मे थे, जिन्होंने सदैव देश की एकता को सर्वोपरि माना। सरदार पटेल ने भारत को खण्ड-खण्ड करने की अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम करते हुए बड़ी ही कुशलता से आजादी के बाद करीब 550 देशी रियासतों तथा रजवाड़ों का एकीकरण करते हुए अखण्ड भारत के निर्माण में सफलता हासिल की थी। राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए स्वतंत्र भारत को एकजुट करने का असाधारण कार्य बेहद कुशलता से सम्पन्न करने के लिए जाने जाते रहे सरदार पटेल का देहांत दिल का दौरा पड़ने के कारण 15 दिसम्बर 1950 को 75 वर्ष की आयु में हो गया था और इसी दिन को प्रतिवर्ष 'सरदार पटेल स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले गृहमंत्री और पहले उप-प्रधानमंत्री रहे सरदार पटेल का भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए अविस्मरणीय योगदान रहा।

सरदार पटेल ने लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की थी। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित हुए और इसीलिए उन्होंने गांधी जी के साथ भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया। वे भाई-भतीजावाद की राजनीति के सख्त खिलाफ थे और ईमानदारी के ऐसे पर्याय थे कि उनके देहांत के बाद जब उनकी सम्पत्ति के बारे में जानकारियां जुटाई गई तो पता चला कि उनकी निजी सम्पत्ति के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। वह जो भी कार्य करते थे, पूरी ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा और हिम्मत से साथ पूरा किया करते थे। उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं, जो इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल प्रशासक के जीवन को समझने में सहायक हैं।

एक किसान परिवार में जन्मे वल्लभ भाई पटेल जब छोटे थे, तब अपने पिताजी के साथ खेत पर जाया करते थे। एक दिन जब उनके पिताजी खेत में हल चला रहे थे तो वल्लभ भाई

पटेल उन्हीं के साथ चलते-चलते पहाड़े याद कर रहे थे। उसी दौरान उनके पांव में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया किन्तु वे हल के पीछे चलते हुए पहाड़े कंठस्थ करने में इस कदर लीन हो गए कि उन पर कांटा चुभने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जब एकाएक उनके पिताजी की नजर उनके पांव में घुसे बड़े से कांटे और बहते खून पर पड़ी तो उन्होंने घबराते हुए बैलों को रोका और बेटे वल्लभ भाई के पैर से कांटा निकालते हुए घाव पर पत्ते लगाकर खून बहने से रोका। बेटे की यह एकाग्रता और तन्मयता देखकर वे बहुत खुश हुए और जीवन में कुछ बड़ा कार्य करने का आशीर्वाद दिया।

वल्लभ भाई पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए सन् 1905 में इंग्लैंड जाना चाहते थे लेकिन पोस्टमैन ने उनका पासपोर्ट और टिकट उनके भाई विठ्ठल भाई पटेल को सौंप दिए। दोनों भाइयों का शुरूआती नाम वी. जे. पटेल था, ऐसे में बड़ा होने के नाते उस समय विट्ठल भाई ने स्वयं इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने बड़े भाई के निर्णय का सम्मान करते हुए न केवल बड़े भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दे दिया बल्कि इंग्लैंड में रहने के लिए उन्हें कुछ धनराशि भी भेजी।

सरदार पटेल का जीवन कितना सादगीपूर्ण था और उनका स्वभाव कितना सहज तथा नम्र था, यह इस किस्से से आसानी से समझा जा सकता है।

सरदार पटेल उन दिनों भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। असेंबली के कार्यों से निवृत्त होकर एक दिन जब वे घर के लिए निकल ही रहे थे, तभी एक अंग्रेज दम्पत्ति वहां पहुंचा, जो विदेश से भारत घूमने के लिए आया था। सरदार पटेल सादे वस्त्रों में रहते थे और उन दिनों उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अंग्रेज दम्पत्ति ने इस वेश में देखकर उन्हें वहां का चपरासी समझ लिया और असेंबली में घुमाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने बड़ी ही विनम्रता से उनका यह

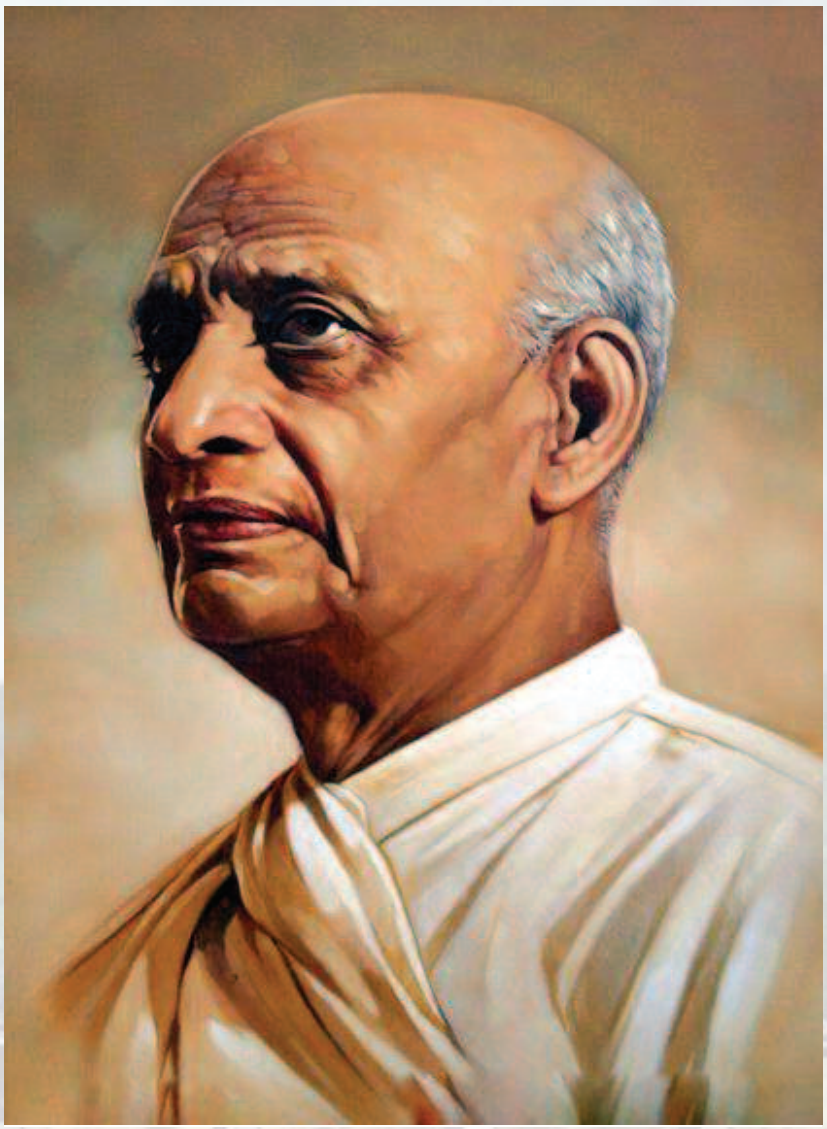

आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें पूरे असेंबली भवन में घुमाया। इससे खुश होकर दम्पति ने सरदार पटेल को बख्शीश में एक रुपया देने का प्रयास किया लेकिन सरदार पटेल ने अपनी पहचान उजागर न करते हुए विनम्रतापूर्वक लेने से इन्कार कर दिया। अगले दिन जब असेंबली की बैठक हुई तो वह अंग्रेज दम्पत्ति लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में पहुंचा और सभापति के आसन पर बढ़ी हुई दाढ़ी तथा सादे वस्त्रों वाले उसी शख्स को देखकर दंग रह गया। वह मन ही मन ग्लानि से भर उठा कि जिस शख्स को चपरासी समझकर उन्होंने उसे असेम्बली घुमाने के लिए कहा, वो कोई और नहीं बल्कि खुद इस असेंबली के अध्यक्ष हैं। अंग्रेज दम्पत्ति सरदार पटेल की सादगी, सहज स्वभाव और नम्रता का कायल हो गया और उसने असेम्बली की कार्रवाई के बाद सरदार पटेल से क्षमायाचना की। एकीकृत भारत की निमार्ता यह महान् शख्सियत 15 दिसम्बर 1950 को चिरनिद्रा में लीन हो गई।

सरदार पटेल ने लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की थी। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित हुए और इसीलिए उन्होंने गांधी जी के साथ भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लिया।

आधुनिक भारत के शिल्पकार
श्रद्धेय अटलजी

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वह पितातुल्य अभिभावक थे। ज्योतिपुंज अटल जी राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह निरहंकारी एवं ध्येयनिष्ठ व्यक्तित्व से लोगों के हृदय में बसे रहे वह देवदुर्लभ है। सहज-सरल, धोती कुर्ता पहने वह लोगों के बीच इतने सामान्य रूप में उपस्थित होते थे कि उनसे मिलने और अपनी बात रखने में कभी किसी कार्यकर्ता या सामान्य जन को जरा भी संकोच नहीं होता था।

भारत रत्न छत्तीसगढ़ के निमार्ता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के ऐसे नायक थे, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने कृतित्व से प्रेरित करते रहेंगे। आज सामाजिक, राजनीतिक एवं समाज जीवन के अनेक क्षेत्र में लक्ष्यावधि लोग अटल जी की प्रेरणा से राष्ट्रकार्य में अपनी श्रेष्ठतम भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं के लिए वह पितातुल्य अभिभावक थे। ज्योतिपुंज अटल जी राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह निरहंकारी एवं ध्येयनिष्ठ व्यक्तित्व से लोगों के हृदय में बसे रहे वह देवदुर्लभ है। सहज-सरल, धोती कुर्ता पहने

सचिन तोमर

वह लोगों के बीच इतने सामान्य रूप में उपस्थित होते थे कि उनसे मिलने और अपनी बात रखने में कभी किसी कार्यकर्ता या सामान्य जन को जरा भी संकोच नहीं होता था। अटलजी के व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रतिभा थी। कवि हृदय लेखक एवं पत्रकार के रूप में उन्हें मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य एवं स्वदेश जैसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत अपनी पत्रकारिता से सिंचने का जो पुनीत कार्य उन्होंने किया वह आज भी देश और समाज को दिशा दे रहा है। एक कुशल राजनेता के रूप में अंत्योदय के वह अहर्निश पुजारी के रूप में आजीवन राष्ट्रसाधना में जुटे रहे। अटल जी आधुनिक भारत के वह महान शिल्पकार थे जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे अंत्योदय के अनुष्ठान से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की अविरल धारा पहुंचाई।

सड़कें किसी भी क्षेत्र की प्रगति की सूचक होती हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं ने दूरस्थ और अभावग्रस्त क्षेत्र तक समृद्धि और अवसर पहुंचाने का काम किया है। सर्वशिक्षा अभियान के जरिए हर बच्चे को स्कूल तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ।

अटल जी के जीवन में राष्ट्र निर्माण के अनुपम सूत्र समाए हुए थे। विपक्ष और अन्य प्रतिस्पर्धी दलों के नेता भी उनसे प्रभावित होते थे तथा उनसे आवश्यक सुझाव लिया करते थे। दलगत भावना से ऊपर उठकर वह राष्ट्रहित में सदैव खड़े रहे। विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाने के कारण राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार उनके भीतर रहा वह आजीवन उनकी कविताओं तथा उनके कृतित्व में प्रकट हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में कई बार लोग मनभेद कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में किसी के प्रति कभी मन में विकार नहीं रहा। उनकी सहजता के कारण ही भिन्न विचारधारा के लोगों में भी उनकी स्वीकार्यता थी। हमारे छत्तीसगढ़ की 31 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय समाज से आती है। देश में कई दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने जनजातीय समाज को हमेशा वोटबैंक की तरह उपयोग किया, लेकिन उनका उत्थान कभी प्राथमिकता में नहीं रहा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में केंद्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की। आज छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर पूर्व समेत विभिन्न राज्यों में जनजातीय समाज के उत्थान हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कथित आर्थिक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। अटलजी का मानना था कि अधोसंरचना विकास किसी भी राष्ट्र की धमनियों की तरह होता है। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्र में निजी क्षेत्र की उद्यमीता को बढ़ावा दिया जो लंबे समय तक गैरप्रतिस्पर्धी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित मान लिए गए थे। इससे देश की अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ।

माननीय अटलजी की दूरदृष्टि से छत्तीसगढ़ के निर्माण का वह संकल्प पूर्ण हुआ जिसके लिए हमारे पुरखों ने लंबा संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के लिए यह वर्ष राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। ऐसे में प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने राज्य निमार्ता अटलजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के प्रत्येक निर्णय में अटलजी के सुशासन का दर्शन होता है। वह चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने से जुड़े अनेक निर्णय हों, जिनमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी, श्रीअन्न, दलहल, तिलहन एवं औषधीय खेती को प्रोत्साहन हो या फिर जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन अन्नदाता के प्रति हमारी प्राथमिकता को साबित करता है।

मातृशक्ति के आर्थिक स्वावलंबन के लिए महतारी वंदन योजना एवं महतारी सदन के निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण राशि एवं चरण पादुका जैसे कल्याणकारी निर्णयों के पीछे मोदी जी गारंटी एवं अटलजी के सुशासन का संकल्प ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन किया है। ई-ऑफिस जैसे नवाचार से शासकीय कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता आई है। दैनिक जीवन से लेकर उद्यम लगाने से जुड़ी गतिविधियों में सहजता हो इस उद्देश्यों से हमारी डबल इंजन सरकार ने लगभग चार सौ नीतिगत सुधार किए हैं। यह छत्तीसगढ़ को सुशासन के बेहतरीन मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करता है।

आज देश के प्रधानसेवक एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी एवं छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं, सकल्प से सिद्धी की यात्रा सही मायने में अटलजी की प्रेरणा से ही संभव होगी। यही उन्हें सच्ची आदरांजलि होगी।

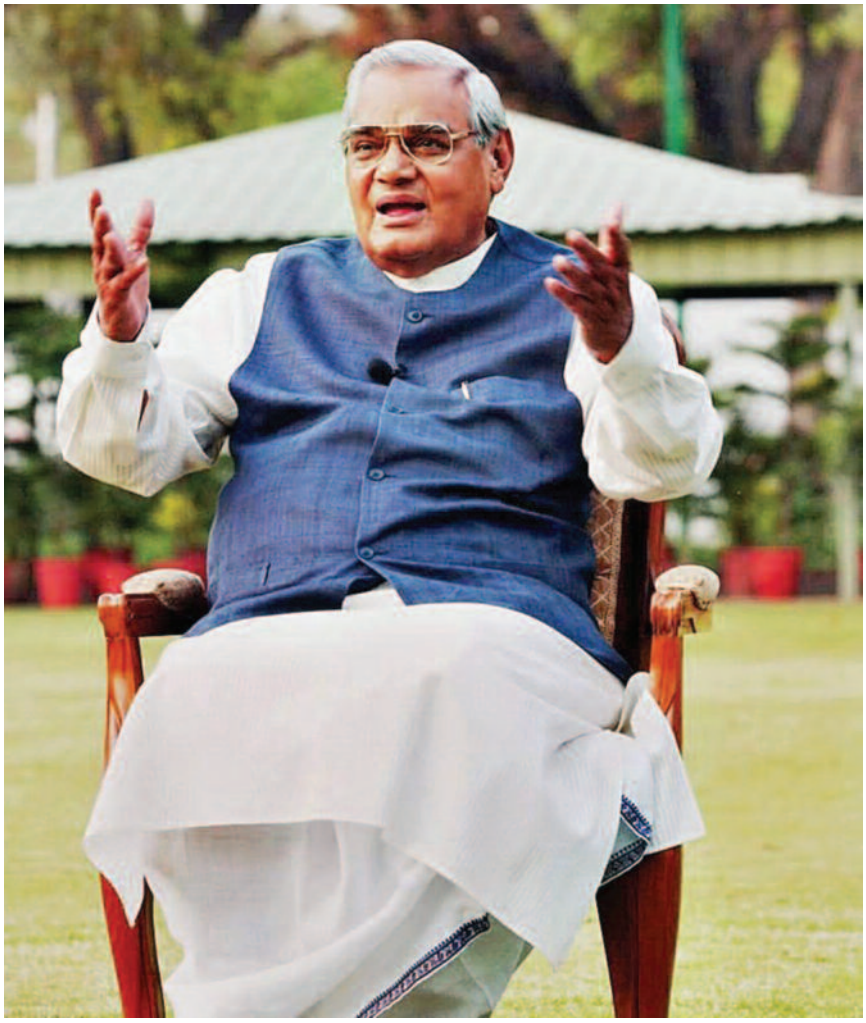

राष्ट्र प्रेरणा स्थल विचार और सेवा का प्रतीकः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

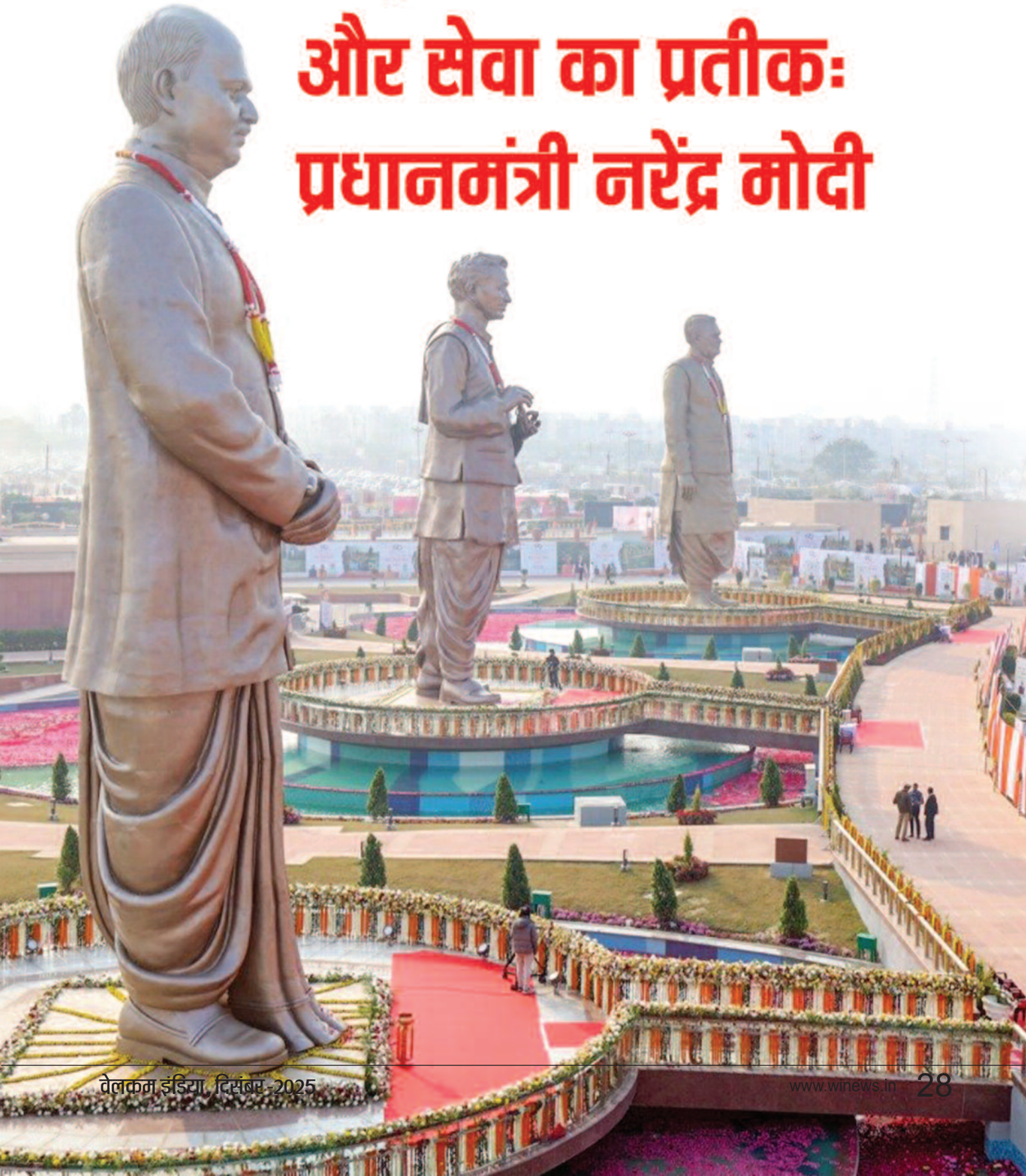

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाओं से युक्त राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। यहां स्थापित प्रतिमाएं राष्ट्र निर्माण के लिए सतत प्रेरणा देती हैं। यह स्थल संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर प्रयास और हर संकल्प राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा।

उत्तर प्रदेश ने विकास और सुशासन की नई पहचान बनाई: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के साथ ही यहां बने भव्य संग्रहालय का भ्रमण भी किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार का फायदा उत्तर प्रदेश को हो रहा है। उत्तर प्रदेश 21वीं सदी के भारत में अपनी अलग पहचान बना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। कभी यूपी की चर्चा खराब कानून व्यवस्था को लेकर होती थी, आज यूपी की चर्चा विकास के लिए होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्रिसमस का यह उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि आज यूपी देश के पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम दुनिया में उत्तर प्रदेश की नई पहचान के प्रतीक बन रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जैसे आधुनिक निर्माण उत्तर प्रदेश की नई छवि को और अधिक रोशन बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश सुशासन, समृद्धि और सच्चे सामाजिक न्याय के मॉडल के रूप में और बुलंदी हासिल करे।

ललित कुमार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 दिसंबर भारत के इतिहास और मूल्यों से जुड़ा अत्यंत प्रेरक दिन है। इसी दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। इन महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी की जन्म जयंती भी है। लखनऊ के समीप स्थित प्रसिद्ध बिजली पासी किला उनकी वीरता, सुशासन और समावेशी विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मरण कराया कि वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। प्रधानमंत्री ने इस पावन अवसर पर महामना मालवीय, अटल जी और महाराजा बिजली पासी को श्रद्धापूर्वक नमन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की अखंडता के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने दो विधान, दो निशान और दो प्रधान की व्यवस्था को सिरे से खारिज किया। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में भारत की अखंडता एक बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा को गर्व है कि उसकी सरकार को अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला और आज जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू है। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉ. मुखर्जी ने औद्योगिक नीति देकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से तय होना चाहिए। उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी के विकास की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस दर्शन को संकल्प में बदला है। आज हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यही सुशासन है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी को परास्त किया है। 2014 से पहले केवल करीब 25 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थे। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 95 करोड़ तक पहुंच चुकी है।प्रधानमंत्री

- बोले पीएम, उत्तर प्रदेश के मेहनतकश लोग लिख रहे नया भविष्य
- राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया, कहा- उत्तर प्रदेश को मिल रहा डबल इंजन सरकार का फायदा
- अटल जी की जन्म शताब्दी पर किया महापुरुषों को याद, परिवारवाद की राजनीति पर करारा प्रहार

जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से हजारों करोड़ रुपये सीधे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे हैं। पहले बैंक खाते और बीमा कुछ ही लोगों के होते थे, हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक बीमा सुरक्षा पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनाई। इससे मामूली प्रीमियम पर 2 लाख तक का इलाज सुनिश्चित हुआ। आज स्कीम से 25 करोड़ से ज्यादा गरीब जुड़े हैं। इसी तरह दुर्घटना बीमा के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है। इससे भी करीब 55 करोड़ गरीब जुड़े हैं। ये पहले बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन योजनाओं से करीब 25 हजार करोड़ रुपए का क्लेम सामान्य गरीब परिवारों तक पहुंचा है। संकट के समय यह पैसा गरीब परिवारों के काम आया।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, अटल बिहारी वाजपेयी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। डिजिटल पहचान, टेलिकॉम क्रांति, सड़क और कनेक्टिविटी की नींव उनकी सरकार के समय पड़ी। उन्होंने कहा कि आज भारत मोबाइल और इंटरनेट का वैश्विक केंद्र बन रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है।

लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था। लेकिन, अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज डिजिटल पहचान की इतना चर्चा हो रही है, इसकी नींव बनाने का काम अटल जी की सरकार ने ही किया था। भारत में टेलिकॉम क्रांति का श्रेय भी अटल जी को जाता है। उनकी सरकार की नीतियों से ही घर-घर तक फोन और इंटरनेट पहुंचना आसान हुआ। आज भारत दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल और इंटरनेट कन्ज्यूमर वाला देश है। आज अटल जी जहां भी होंगे, इस बात से प्रसन्न होंगे कि बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निमार्ता बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, जिस यूपी से अटल जी सांसद रहे वह यूपी आज भारत का नंबर वन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राज्य है। कनेक्टिविटी को लेकर अटल जी के विजन ने 21वीं सदी के भारत को शुरूआती मजबूती दी। अटल जी की सरकार के समय ही गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया था। उसी समय स्वर्णिम चतुर्भुज यानी हाइवे के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 2000 के बाद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनी हैं। इनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पिछले 11 साल में बनी हैं। आज हमारे देश में अभूतपूर्व गति से एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा है। हमारा यूपी भी एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वे अटल जी ही थे जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो की शुरूआत की थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क लाखों लोगों का जीवन आसान बना रहा है। भाजपा में एनडीए सरकार ने सुशासन की जो विरासत बनाई है उसे आज भाजपा की केन्द्र और राज्य की सरकारें नया आयाम-नया विस्तार दे रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक एक ही परिवार के नाम पर इतिहास और उपलब्धियों को सीमित करने की प्रवृत्ति रही। भाजपा ने इस सोच को बदला है। परिवार की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। ये असुरक्षा से भरी हुई है। खुद की पीढ़ियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है। ताकि, उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआ-छूत का चलन शुरू किया। आजाद भारत में अनेक प्रधान मंत्री हुए लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने एनडीए ने ही बदला है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। चाहें किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना ही छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनी

तिक रूप से भाजपा को अछूत बनाए रखा। लेकिन, भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। बीते 11 वर्षों में नरसिम्हा राव जी व प्रणव बाबू को भारत रत्न दिया गया। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव और तरुण गोगोई जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता है। इन लोगों के राज में तो भाजपा के नेताओं को केवल अपमान ही मिलता था।

डॉ. मुखर्जी जी, पं. दीनदयाल जी व अटल जी की विरासत ने भारत को दी नई दृष्टिः सीएम योगी

पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीन दयाल उपाध्याय और अटलजी की विरासत ने भारत को नई दृष्टि दी। आज उनके सपने साकार हैं जिसे देख हर भारतवासी प्रफुल्लित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डा. मुखर्जी, पं. दीनदयाल व भारत रत्न अटलजी की 65-65 फिट ऊंची कांस्य प्रतिमा और डिजिटल म्यूजियम का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का उद्घोष किया था और आज ऐसा हो चुका है वहीं पं. दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के भारत में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में भी नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य नागरिक के रूप में जीवनयापन कर रहे हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने वाले, श्रद्धेय अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले आत्मनिर्भर व आधुनिक भारत के शिल्पकार, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के स्वप्न द्रष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल, तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमा व म्यूजियम का भव्य लोकार्पण हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर व विकसित भारत का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, उसमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी का मार्गदर्शन प्रेरणा के रूप में है।

अनादि शुक्ल

सीएम योगी ने कहा कि यह अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। अटल जी कहते थे कि 'अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा', यह केवल आशा नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य को लेकर उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि व दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। अटल जी ने कवि, पत्रकार, राष्ट्रवादी विचारक व भारत के सच्चे सपूत के रूप में देश को जो विजन-नेतृत्व दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विकास व विरासत के नए रूप में देख रहा है। आज के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी के करकमलों से राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्राप्त हो रहा है।

सीएम योगी ने भारत माता के सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व महान शिक्षाविद् महामना पं. मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर याद किया। बोले कि मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें 'भारत रत्न' देकर प्रधानमंत्री जी ने उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजा बिजली पास को भी नमन किया और कहा कि महान योद्धा बिजली पासी से भी हर भारतीय को नई प्रेरणा प्राप्त होती है।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे।

सशक्त, स्वाभिमानी व स्वावलंबी भारत बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं पीएम मोदी: रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दशक में देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है, उनमें 'अपने महापुरुषों-विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, उनका सम्मान व संरक्षण करना' भी है जिसे पीएम मोदी ने दिया है। इस सोच से प्रभावित होकर राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भारत के तीन ऐसे महापुरुषों (पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी) की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं। इन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान व नई पहचान दिलाने का कार्य किया। रक्षा मंत्री ने प्रख्यात मूर्तिकार रामसुतार के प्रति श्रद्धांजलि और दो प्रतिमा बनाने वाले मांटू राम के प्रति सम्मान प्रकट किया। रक्षा मंत्री ने शानदार प्रेरणा स्थल यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी।

रक्षा मंत्री ने पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति श्रद्धा निवेदित की। उन्होंने पं. महामना मदन मोहन मालवीय का भी स्मरण किया। कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारत की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया। जम्मू-कश्मीर को धारा-370 के तहत विशेष दर्जा मिला था, उसे समाप्त करने के लिए डॉ. मुखर्जी ने प्राणों की आहुति दी। पीएम मोदी ने आजाद भारत ने उनके संकल्प को पूरा किया। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद व अंत्योदय का विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने जो विचारधारा दी, उसी आधार पर पीएम मोदी सशक्त, स्वाभिमानी व स्वावलंबी भारत बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। पं. उपाध्याय का मानना था कि व्यक्ति के मान, सम्मान व स्वाभिमान की भी चिंता की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन का सार बताते हुए कहा कि तन के सुख के लिए धनधान्य, मन के सुख के लिए मान, सम्मान व स्वाभिमान, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार गरीब

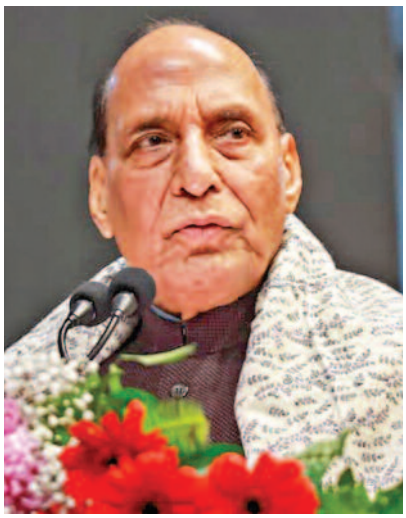

कल्याण की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त कर रही है तो उसके पीछे हमारी प्रेरणा पं. दीनदयाल उपाध्याय हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र के लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से घुले-मिले थे। सभी उनके विनोदी स्वभाव से परिचित हैं। रक्षा मंत्री ने अटल जी के पाकिस्तान दौरे से जुड़ी घटना सुनाते हुए उनकी हाजिर जवाबी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति, समाज, संस्कृति के विकास में अटल जी का योगदान अतुलनीय है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने गांव, गरीब, किसानों के लिए बड़ा काम किया है। पहले मनरेगा में तरह-तरह की धांधली होती थी, उसके स्थान पर जी राम जी के नाम पर संसद में नया विधेयक पारित किया है। पहले श्रमिकों को 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। साथ ही गांवों में स्थानीय बुनियादी ढांचों का विकास भी होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की नई बुलंदियों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार महंगाई की दर एक फीसदी के नीचे गई है। पीएम मोदी के शासनकाल में 8 फीसदी से अधिक की विकास दर दिख रही है।

एसआईआरः मतदाताओं के सत्यापन के बीच सता रहा वोट रद्द होने का डर

लोगों में वोट रद्द होने का बढ़ रहा है डर

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा भी परेशानी महसूस करने लगी है। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब देश के 12 और राज्यों में इसकी शुरूआत हो गई है। एसआईआर होने से वास्तविक मतदाताओं की पहचान होगी और फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया जा सकेगा। बिहार में यह आंकड़ा 65 लाख के आसपास बताया गया है। एसआईआर शुरू होने से उन लोगों में खासा हड़कंप मचा हुआ है, जो कहीं और के रहने वाले हैं। इसके अलावा एसआईआर में शिक्षकों को लगाया गया है, लेकिन निकायों के उन कर्मचारियों को नहीं लगाया गया

अनिल वशिष्ठ

है जो क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। नगर निकायों की बात करें तो कर अधीक्षक और उनकी टीम को क्षेत्र के एक-एक घर के बारे में पूरी जानकारी होती है, लेकिन उन लोगों को एसआईआर में नहीं लगाया गया है। वहीं, भाजपा में जिन नेताओं ने पन्ना प्रमुख बनकर अखबारों में अपनी फोटो छपवाई थीं, वह भी नदारद ही हैं। बीएलओ बनाए गए शिक्षकों पर इतना दबाव है कि वह सहन नहीं कर पा रहे हैं। देश भर से बीएलओ की मौतों की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। भले ही एसआईआर से वास्तविक मतदाताओं की पहचान होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में भाजपा अपना कैडर वोट भी खो सकती है।

क्या है एसआईआर

निर्वाचन आयोग ने जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की घोषणा की, वहां लोगों द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद प्रकाशित बिहार की मतदाता सूची और आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है। देश के 12 राज्यों में चार नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई डै। एसआईआर

का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान कर मतदाता सूची से उनका नाम हटाना है। अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित की जाएगी, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि के लिए आमतौर पर अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। जब इस जन्म वर्ष में 18 साल जोड़े जाते हैं, तो यह अवधि 2002-2004 के बीच आती है। यही कारण है कि 2003-04 की मतदाता सूची को नागरिकता सत्यापन के लिए एक मानक दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। जिनका नाम उस सूची में दर्ज है, उनकी नागरिकता की जांच की आवश्यकता नहीं मानी जा रही है। इसी वजह से पिछले एसआईआर से इनका मिलान किया जा रहा है।

असम में एसआईआर पर क्या अपडेट

'नागरिकता अधिनियम के तहत, असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान हैं। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसी परिस्थितियों में यह असम पर लागू नहीं होता। इसलिए असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और एसआईआर की एक अलग तिथि घोषित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मौजूदा एसआईआर स्वतंत्रता के बाद से ऐसी नौवीं कवायद है और पिछला एसआईआर 21 वर्ष पहले 2002-04 में हुआ था।

एसआईआर पर टीएमसी को आपत्ति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ किसी भी टकराव की स्थिति बनने से भी इनकार किया। प्रदेश की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं। कुमार का कहना था कि निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। आयोग एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देकर अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहा है और राज्य सरकार भी अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के लिए आयोग को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं।

बिहार में एसआईआर का काम पूरा

स्थानीय निकाय चुनावों के कारण केरल में एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग पर, कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। बिहार में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम पूरा हो चुका है, जहां लगभग 7.42 करोड़ मतदाताओं की अंतिम सूची बीते 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी। राज्य में मतदान दो चरणों में होगा छह नवंबर और 11 नवंबर को होगा तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयोग एसआईआर कराने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ पहले ही दो बैठकें कर चुका है। कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद की मतदाता सूचियां अपनी वेबसाइटों पर डाल दी हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में अंतिम एसआईआर 2006 में हुआ था और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. राज्यों में अंतिम एसआईआर उसी तरह से 'कट-ऑफ' तिथि के रूप में काम करेगी जैसे बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची का उपयोग चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण के लिए किया था। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच था और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में हुए अंतिम एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया है।

एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य

एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों की जांच करके उनका नाम मतदाता सूची से बाहर करना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न देश के अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ढूंढ लीजिए इन 13 में से कोई एक दस्तावेज

चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 12 दस्तावेजों में एक और दस्तावेज को मान्यता दे दी है। अब बिहार एसआईआर-2025 वोटर लिस्ट भी देश भर के लिए होने वाले एसआईआर में मान्य होगी। यानी अब मान्य दस्तावेजों की लिस्ट में 13 दस्तावेज हो गए हैं। हालांकि, 12वें दस्तावेज के रूप में मान्य किए गए आधार को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट

किया कि आधार ना तो जन्म प्रमाण पत्र का आधार है और ना ही निवास का। यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है। यह केवल पहचान है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आधार को लेकर देशभर में बन रही भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह कहा।

इनमें से कोई न कोई प्रूफ देना होगा

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नए युवा वोटर और ऐसे वोटर्स जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस से संबंधित दस्तावेज जमा कराना है। अगर वह एनुमरेशन फार्म के साथ केवल आधार की कॉपी जमा कराते हैं तो ऐसे फार्म मान्य नहीं होंगे। वोटर को अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस को प्रमाणित करने के लिए आधार के अलावा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों में से कोई ना कोई देना होगा। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि ऐसे वोटर, जो अपने माता-पिता वाले घर से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी कोई ना कोई प्रूफ देना होगा। अगर वह अपने पैतृक घर में ही रह रहे हैं और उनके माता-पिता का नाम एसआईआर वाली लिस्ट में है तो उन्हें केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि उनका खुद का नाम अंतिम एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में है तो उन्हें एक भी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि अब चूंकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में बिहार की एसआईआर-2025 वोटर लिस्ट को भी 13वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसका फायदा उन वोटरों पर पड़ेगा, जो बिहार से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में उनके माता-पिता का नाम अगर बिहार वाली इस वर्तमान एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में है तो उन्हें केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र और जहां रह रहे हैं। उसका कोई दस्तावेज देना होगा। बर्थ प्लेस का सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं होगी।

इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

चूंकि देश में लंबे समय से एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई थी। ऐसे में राज्यों की वोटर लिस्ट को शुद्ध करना बेहद जरूरी था। इसी वजह से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर शुरू करने का यह बीड़ा उठाया। जिसके तहत पहले चरण में बिहार में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी गई है। तीसरे चरण में बाकी बचे राज्यों में इसे शुरू किया जाएगा।

इसे लेकर क्या विवाद है?

बिहार में एसआईआर को लेकर काफी विवाद हुआ। कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर का विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने जैसा गंभीर आरोप लगाया। दलों का कहना है कि एसआईआर से गरीब और टारगेट करके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। जबकि बिहार में एसआईआर के बाद जब 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई। तब से अब तक एक भी वोटर ने चुनाव आयोग पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि उसका नाम गलत तरीके से काट दिया गया।

गणना फॉर्म कैसे भरना है?

मतदाताओं के पास अपना विवरण भरने के लिए 7 से 10 दिन का समय होगा। प्रत्येक मतदाता को अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और माता-पिता या पति-पत्नी का नाम देना होगा।

वितरण पूरा होने के बाद, बीएलओ फिर से प्रत्येक घर जाकर भरे हुए ईएफ फॉर्म एकत्र करेगा। संग्रह के दौरान इन बातों का रखें ध्यान-

- बीएलओ प्रत्येक भरे हुए फॉर्म को मोबाइल ऐप के माध्यम से स्कैन करेगा।
- स्कैन करने पर ऐप तुरंत मतदाता की जानकारी को कैप्चर कर लेता है और उसे उनके वोटर आईडी कार्ड से जोड़ देता है।
- अपडेट सफल होने का संकेत तब मिलता है जब ऐप हरे रंग में चमकता है, जिससे पुष्टि होती है कि मतदाता उस क्षेत्र में रहता है और मास्टर इलेक्टोरल डेटाबेस में डेटा को सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है।
- यह डिजिटल प्रक्रिया स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करती है, जिससे दोहराव को समाप्त करने और धांधली या प्रतिरूपण को रोकने में मदद मिलती है।

मतदाता सूची का प्रकाशन

- जिन मतदाताओं ने अपना ईएफ जमा कर दिया है, उन्हें यह सत्यापित कर लेना चाहिए कि उनका नाम सूची में है।
- यदि उनका नाम सही दिखाई देता है तो उनकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, उन्हें सुधार या नाम शामिल करने का दावा करने के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ से संपर्क करना होगा।
- ईआरओ ऐसे मामलों की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। इस चरण को 'सुनवाई और सत्यापन' अवधि कहा जाता है।

एसआईआर की अभी जरूरत क्यों?

हमारे जैसे घनी आबादी वाले देश में, जहां रोजगार और अन्य कारणों से प्रवास और पुनर्वास अक्सर होता रहता है, हर चुनाव से पहले मतदाता

सूची का पुनरीक्षण एक जरूरी काम बन जाता है। दुर्भाग्यवश, अतीत में इस प्रथा का लगातार या पूरी लगन से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई योग्य मतदाताओं को चुनाव के दिन निराशा का सामना करना पड़ा। उनके नाम मतदाता सूची से गायब थे। समान रूप से चिंताजनक बात यह है कि मृत व्यक्तियों के नाम समय पर नहीं हटाए गए, जिसके कारण कभी-कभी गलतियां और अनियमितताएं हो जाती हैं और इससे डाले गए मतों का प्रतिशत और कुछ मामलों में तो चुनाव परिणाम भी विकृत हो जाते हैं। पिछला व्यापक संशोधन लगभग दो दशक पहले किया गया था। तब से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है और तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के साथ-साथ, बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवास भी हुआ है।

ये जनसांख्यिकीय और सामाजिक परिवर्तन मतदाता सूची को अपडेट करना और भी जरूरी बना देते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता ही होंगे। इसका संचालन एक बीएलओ द्वारा किया जाएगा। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए आधार दस्तावेज 2002-2004 की सूची है। जिन मतदाताओं के नाम पुरानी सूची में हैं, उनके लिए सत्यापन प्रक्रिया आसान होगी।

मतदाताओं को दी गई सलाह

ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन के साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और शामिल न किए गए डुप्लिकेट नामों की सूची सीईओ की वेबसाइट और सार्वजनिक कार्यालयों में उपलब्ध होगी। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने विवरण सत्यापित कर लें। यदि कोई दावा या आपत्ति हो तो उसे ईआरओ या बीएलए के पास दर्ज कराया जाना चाहिए।

ये हैं खामियां

एसआईआर की पूरी जिम्मेदारी बीएलओ बनाए गए शिक्षकों के कंधों पर डाल दी गई है। उनके सहयोग के लिए स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता तक नहीं आ रहे हैं। बीएलओ बने शिक्षकों को जो क्षेत्र सौंपा गया है, उसकी उन्हें भौगोलिक जानकारी तक नहीं है। इसके अलावा क्षेत्र में रहने वालों को भी वह नहीं जानते। उन पर जल्द से जल्द काम पूरा करने का दबाव है। जिसके कारण बीएलओ तनाव में आ रहे हैं। देश भर में 10 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। लेकिन, उनके परिवारों को किसी तरह की आर्थिक सहायता का आश्वसन तक नहीं दिया गया है। जबकि किसी भी क्षेत्र से सबसे ज्यादा परिचित होता है हाउस टैक्स वसूल करने वाला कर्मचारी। उसे न केवल क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान होता है बल्कि उसे क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोगों की भी जानकारी होती है। बीएलओ के साथ यदि कर वसूलने वाले कर्मचारियों को भी लगा दिया जाता तो यह कार्य सुगमता से हो सकता था।

ये हो सकता है नुकसान

एसआईआर को यदि उत्तर प्रदेश के नजरिये से देखें तो इसका बड़ा खामियाजा भाजपा को ही उठाना पड़ सकता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से मतदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आते हैं। जो गांव छोड़कर काम की तलाश में शहरों में आकर बस गए हैं।

एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाता अपना मताधिकार गांव का ही रहना चाहते हैं। फिर भले ही वह गांव जाकर मतदान न करें। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पलायन बहुत ज्यादा है। रहने का स्थान बदलने के कारण ऐसे मतदाता एसआईआर में शामिल होने से वंचित रह सकते हैं और उनका वोट कट सकता है। जबकि मुस्लिम इलाकों में ऐसी समस्या नहीं है। जो जहां रह रहा है वह दशकों से वहीं रह रहा है।

बीजेपी की चिंता के कारण

शहरी वोटों का पलायनः बीजेपी की चिंता का बड़ा कारण शहरी वोटरों का पलायन है।

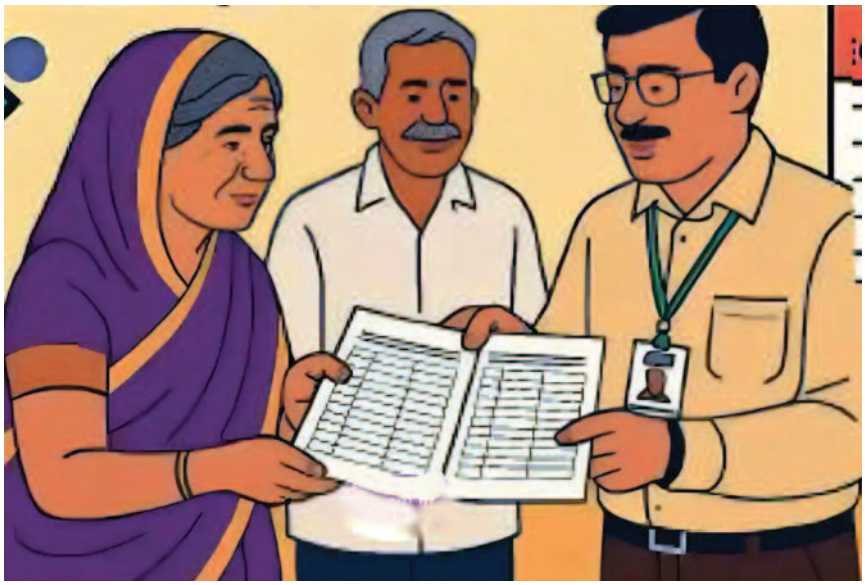

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी का कोर बेस कमजोर होने का डर सता रहा है। बीजेपी को लगातार शहरी क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 17 शहरी सीटों में से 12 जीतीं। 2022 विधानसभा चुनाव में 86 शहरी सीटों में से 65 उसके खाते में आईं। नगर निकाय चुनाव 2023 में सभी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ऐसे में शहरी वोटर का गांव जाना सीधे तौर पर चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। वोटरों के मिजाज का डरः बीजेपी को वोटरों के मिजाज का डर सता रहा है।

दरअसल, कहा जा रहा है कि वोटर तो गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मतदान करने गांवों में नहीं जाएंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि शहरी मतदाता आमतौर पर मतदान के दिन कम सक्रिय होते हैं। अगर उन्होंने वोट गांव में शिफ्ट कर लिया, तो वे 50-200 किलोमीटर दूर गांव जाकर वोट डालने की संभावना कम है।

इससे बीजेपी को सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये वोटर उसका मजबूत सपोर्ट बेस माने जाते हैं। ग्रामीण वोटरों में प्रॉपर्टी को लेकर डरः यूपी एसआईआर के दौरान शहरी वोटरों के गांवों की तरफ पलायन का एक बड़ा कारण प्रॉपर्टी का डर माना जा रहा है। दरअसल, कई शहरी परिवारों की गांव में पुश्तैनी जमीन होती है। लोगों में यह आशंका है कि अगर वे गांव के वोटर नहीं रहे तो कहीं उनका जमीन पर मालिकाना हक कमजोर न हो जाए। यही भ्रम कई परिवारों को अपना नाम गांव में जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कितने शहरी वोटरों का गांव पलायन

राजधानी लखनऊ के 21.73 लाख शहरी वोटरों में से करीब 10-12 फीसदी यानी करीब 2.6 लाख वोटर अपने गांव का पता चुन रहे हैं। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चिंतित दिखे और उन्होंने राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से चर्चा की। संगम नगरी प्रयागराज के लगभग 2 लाख वोटर ग्रामीण पते पर शिफ्ट होने का विकल्प चुन चुके हैं। 2024 में यहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। अब वोटों का यह भारी बदलाव पार्टी के लिए भविष्य में और बड़ी चुनौती बन सकता है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के करीब 41,000 वोटरों ने गांव का पता चुना है। 2024 में यहां बीजेपी को करारी हार मिली थी। ऐसे में यह बदलाव चिंताएं और बढ़ाता है।

क्यों बदल रहे अपना पता?

शहरी वोटरों के अपने ग्रामीण क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के पीछे का सबसे बड़ा कारण पुश्तैनी जमीन खोने का डर माना जा रहा है। इसके अलावा गांव में रिश्तेदारी या परिवार की मौजूदगी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय चुनावों पर प्रभाव रखने की इच्छा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बढ़ते किरायेदारी आधारित जीवन और अस्थाई निवास के कारण वे गांवों के स्थायी पते को आधार बनाने की कोशिश में हैं।

बीजेपी नेतृत्व हुआ सक्रिय

यूपी एसआईआर सर्वे रिपोर्ट का मामला गंभीर होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद और विधायकों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और एसआईआर पर पूर्ण फोकस का निर्देश दिया। पार्टी ने अपने नेताओं को यहां तक कहा है कि शादी-ब्याह में शामिल होने की बजाय अगले कुछ दिनों तक एसआईआर पर ध्यान दें। कई नेताओं को काम पर लगाया गया है। धर्मपाल सिंह ने 3 दिसंबर को वाराणसी में 4 बैठकें, 5 दिसंबर को आगरा-मथुरा में समीक्षा की।

केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज, कौशांबी, मिजार्पुर और झांसी में बैठकों की झड़ी लगा दी। ब्रजेश पाठक नोएडा, गाजियाबाद, बाराबंकी, सीतापुर में रक्फ़की प्रगति देख रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और जौनपुर का दौरा किया। सूत्रों के अनुसार, धर्मपाल सिंह ने कई नेताओं को रक्फ़में रुचि न लेने पर फटकार भी लगाई।

बीजेपी ने बनाई अलग रणनीति

लखनऊ के एक बीजेपी नेता के अनुसार, वे मतदाताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर पूरा परिवार गांव का पता नहीं छोड़े तो कम से कम एक सदस्य का वोट शहर में रहने दें, ताकि शहरी वोट कम न हो। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर शहरी मतदाताओं का यह ट्रेंड जारी रहा तो 2027 में शहरी सीटों पर पार्टी की पकड़ ढीली हो सकती है, जहां ऐतिहासिक रूप से वह सबसे मजबूत रही है। 2024 में शहरी सीटों पर सपा और कांग्रेस ने थोड़ा उभार दिखाया था। अगर लाखों वोट गांव की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो शहरी मुकाबले स्वाभाविक रूप से तीन-कोणीय या टफ हो सकते हैं।

सड़क हादसों की बढ़ती वजह: अवैध पार्किंग और हाईवे किनारे ढाबे

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

सड़क हादसे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हैं, जो पल भर में हँसते-खेलते परिवारों को उजाड़ देती हैं। इनमें किसी अपने की जान जाना या जीवन भर की अपंगता पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल देती है। हादसे के बाद केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा भी लंबे समय तक बनी रहती है। बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है और बुजुर्ग सहारे से वंचित हो जाते हैं। समाज पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि कार्यशील नागरिकों की क्षति से सामाजिक-आर्थिक विकास बाधित होता है। अस्पतालों और आपात सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इन हादसों का सबसे दुखद पहलू यह है कि अधिकांश दुर्घटनाएं थोड़ी-सी सावधानी और नियमों के पालन से रोकी जा सकती हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा को केवल कानून नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में समझना जरूरी है।

घना कोहरा व धुंध सड़क हादसों का प्रमुख कारण

हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास 16 दिसंबर 2025 मंगलवार तड़के कोहरा 13 लोगों के लिए काल बन गया। दरअसल, कोहरे के कारण दृश्यता शून्य होने के कारण आपस में टकराने से वाहनों में आग लग गई, जिससे यात्री जिंदा जलकर मर गये। जानकारी के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि सौ से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। वास्तव में, घने कोहरे के कारण आगे चल रहा वाहन डिवाइडर से टकराकर संतुलन खो बैठा और इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन एक के बाद एक टकराते चले गए। इससे वाहनों में आग लग गई। गहरी नींद में सो रहे यात्रियों की तेज आवाज से आंख खुली तो चीख-पुकार मच गई और वे जान बचाने के लिए जलते वाहनों से कूदने लगे। आशंका है कि सीएनजी वाहन में विस्फोट से आग लगी। दमकलों ने जब तक आग पर काबू पाया, 14 वाहन जल चुके थे। इनमें आठ बसें और एक कार शामिल है। ये बसें यूपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आ रही थीं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि, 'मेरी संवेदनाएं अपनों को खोने वाले परिवारों के साथ हैं।' भीषण हादसे के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख और

आंकड़े बयां करते हैं सड़क हादसों की भयावहता

हाल फिलहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो 2025 में भारत में सड़क हादसों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उपलब्ध सरकारी व मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी से जून 2025 के बीच केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही लगभग 67,900 से अधिक सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें करीब 29,000 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा दशार्ता है कि हर दिन औसतन 150 से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और सड़क किनारे अव्यवस्थित ढाबे-पार्किंग जैसी समस्याएँ इन हादसों के प्रमुख कारण बने हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यही रुझान जारी रहा, तो 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है, जो सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वास्तव में आज देश में सड़कें तो तेजी से बन रही हैं, लेकिन उन पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने को उतनी गंभीरता नहीं दी जा रही। हादसों के कारण बार-बार सामने आने के बावजूद ठोस नीति और सख्त नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं। अगर समय रहते अवैध ढाबों, पार्किंग व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे और देश को जान-माल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

मीडिया में आईं खबरों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 महिलाओं और 4 बच्चों सहित कुल 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान एनएचएआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नेशनल हाइवेज अथारिटी ऑफ इंडिया) और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई।

घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद देने का ऐलान किया है।

सड़क हादसों के लिए वाहन चालकों की लापरवाही ही जिम्मेदार नहीं

हाल फिलहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर जो बड़े सड़क हादसे हुए हैं, उनके लिए सिर्फ वाहन चालकों की लापरवाही ही जिम्मेदार नहीं है। सच तो यह है कि सड़क किनारे बने ढाबे और होटल भी इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। अक्सर इन ढाबों के सामने ट्रक, बस या अन्य वाहन सड़क के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं और सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां उन्हें समय पर देख नहीं पातीं और उनसे टकरा जाती हैं। इसका गंभीर उदाहरण कुछ समय पहले ही राजस्थान के फलोदी में हुआ एक हादसा है, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टेम्पो ट्रैवलर टकरा गया। मीडिया में आईं खबरों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 महिलाओं और 4 बच्चों सहित कुल 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान एनएचएआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नेशनल हाइवेज अथारिटी ऑफ इंडिया) और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई।

अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारे बने अवैध ढाबे और होटल सड़क हादसों की बड़ी वजह हैं और इन्हें रोकने के लिए देशभर में लागू होने वाले नियम बनाने की जरूरत है। वास्तव में, असल समस्या यह है कि कई ढाबे और होटल लाभ कमाने के उद्देश्य से बिना पर्याप्त पार्किंग के ही सड़क किनारे

खोल दिए जाते हैं और वहां ठहरने वाले लोग मजबूरी में अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जबकि इन सड़कों पर वाहन बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं।

ऐसे में हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। सवाल यह है कि ऐसे ढाबों को बिना नियम-कानून के चलने की इजाजत किसने दी और अब तक सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की ? क्या ऐसे ढ़ाबा व होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए ? यह विडंबना ही है कि आज हमारे देश में सड़क किनारे खुलने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल अक्सर बिना किसी ठोस नियम-कानून के संचालित हो रहे हैं। ये जहां जगह मिल गई, वहीं बना दिए जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। अधिकांश ढाबों के सामने वाहनों की अवैध पार्किंग रहती है, या बहुत से स्थानों पर तो पार्किंग व्यवस्थाएं होतीं ही नहीं हैं, ऐसे में वाहनों को यत्र-तत्र अव्यवस्थित रूप से पार्क करना पड़ता है, जो सड़क हादसों का कारण बनती है।

वास्तव में ऐसी जगहों पर न तो यहां सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था होती है और न ही प्रवेश-निकास के लिए निर्धारित स्थान। कई जगहों पर तो पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। इससे यात्रियों को, वाहन चालकों को परेशानी होती है और आसपास गंदगी भी फैलती है। यह एक कड़वा सच है कि स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जाती है। जरूरत है कि ऐसे ढाबों और होटलों के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं और उनका सख्ती से पालन कराया जाए।

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की जिम्मेदारी पूरे समाज की है

बहरहाल, यहां यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में दिसंबर-जनवरी ठंड के महीने होते हैं और इस दौरान देश के कई हिस्सों, विशेषकर पानी वाले इलाकों में घना कोहरा व धुंध छा जाती है, जिससे सड़क पर दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसे हालात में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना अनिवार्य है। मोबाइल फोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान भटकाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ाता है। शराब या किसी भी प्रकार के नशे में वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है। यदि नींद या थकान महसूस हो रही हो तो वाहन रोककर विश्राम करना ही सुरक्षित विकल्प है। इसके साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, गति सीमित रखनी चाहिए और सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि यह दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है। वास्तव में, सावधानी और जिम्मेदारी ही ठंड व कोहरे के मौसम में सुरक्षित यात्रा की कुंजी है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि यह हमारे पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिकतर सड़क हादसे तेज गति, नशे में ड्राइविंग, मोबाइल फोन के प्रयोग और यातायात के नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट, लेन ड्राइविंग और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने से दुर्घटनाओं में भारी कमी लाई जा सकती है। सड़कों की खराब स्थिति, अव्यवस्थित पार्किंग और अतिक्रमण भी हादसों को बढ़ावा देते हैं। सरकार, प्रशासन और नागरिकों सभी को मिलकर सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। जागरूकता अभियान, सख्त कानून और उनका ईमानदार क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। सुरक्षित सड़कें केवल नियमों से नहीं, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार से बनती हैं। यदि समय रहते सावधानी बरती जाए, तो अनमोल जानें बचाई जा सकती हैं।

देश की राजधानी किसी बुरे सपने से कम नहीं है

मनोज शर्मा

सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है।

देश में वोट बैंक की राजनीतिक के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। राजनीतिक दल इसे समस्या तो मानते हैं किन्तु इसके स्थायी निदान के लिए न तो कोई कार्ययोजना है और न ही इच्छाशक्ति। देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है। यही वजह है कि प्रदूषण की भयावहता तमाम क्षेत्रों में तरक्की को मुंह चिढ़ा रही है। सरकारों और राजनीतिक दलों की बला से प्रदूषण प्रभावित इन क्षेत्रों के करोड़ों लोगों बेशक तिल–तिल करके मरते रहें। इसके विपरीत नेताओं का सरोकार सिर्फ चुनाव जीतने भर तक सीमित रह गया है। सत्तारुढ़ और विपक्षी दल इस मुद्दे पर चिंता जताने तक सीमित हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत में विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपने चेहरों पर मॉस्क लगाया और प्रदूषण के खिलाफ नारे लिखे तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। एक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी जिस पर लिखा था 'मौसम का मजा लीजिए'।

सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। दिल्ली का औसत एक्यूआई लेवल 377 तक दर्ज हो चुका है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या देखने को मिल रही है। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक जहांगीर पुरी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नेहरू नगर में एक्यूआई लेवल 400 के पार तक पहुंच गया। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम कब होगा। इस सवाल का जवाब इस समय शायद किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि बच्चों की सेहत ठीक रखना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए।

दिल्ली में एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण ट्रांसपोर्ट, पराली है। गाड़ियों से फैले प्रदूषण का हिस्सा 18.42% था। आंकड़ों के हिसाब से 16.31% प्रदूषण के अन्य सोर्स हैं, जिसमें आतिशबाजी, डीजल जनरेटर जैसे सोर्स शामिल है। शादियों के सीजन की वजह से आतिशबाजी हो भी रही हैं। अगले तीन दिन इन अन्य सोर्स का प्रदूषण का हिस्सा और बढ़कर 43.4% तक जाने का अनुमान है। दिल्ली में एक्यूआई 400 तक के खतरानक स्तर को छू चुका है, जो वायु प्रदूषण की गंभीर हालत दिखाता है। वहीं मुंबई में भी ये 200 के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद वहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप 4) लागू किया गया। हालांकि दिल्ली में अभी ग्रैप 4 लागू नहीं किया गया। उल्टे दिल्ली एनसीआर में 26 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां भी वापस ले ली गई थीं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शहर में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। देवनार, मलाड, बोरीवली, अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड जैसे इलाकों में प्रदूषण की खराब स्थिति के बाद ये फैसला लिया गया था।

दिल्ली में प्रदूषण पराली जलने, वाहनों के धुएं और कारखानों से निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है। हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से हालात और खराब हो जाते हैं। हालांकि मुंबई और अन्य समुद्री इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहतर रहती है, क्योंकि वहां हवा चलने के कारण प्रदूषणकारी तत्व शहर से दूर चले जाते हैं। मुंबई में मेट्रो, फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण कार्य, वाहनों की बढ़ती तादाद और कचरा जलाने जैसी वजहों से हालत बिगड़ी है। मुंबई जैसे समुद्री इलाकों में एक्यूआई बढ़ना खतरे की घंटी है। मुंबई में ग्रैप-4 की पाबंदियों के बाद एक्यूआई 150 से नीचे आ गया, जबकि दिल्ली की हवा में अब भी दम घुट रहा है। मुंबई की हवा अब सांस लेने लायक हो गई है। यहां कई जगह एक्यूआई लेवल 100 के आसपास हो गई। हालांकि, दिल्ली में एक्यूआई लेवल अब भी कई जगह 400 के पार है। हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में एक्यूआई स्तर 150 से नीचे आने में मदद मिली। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था आईक्यूएआईआर की नवीनतम लाइव रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली इस सूची में पहले स्थान पर रही। जबकि दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद 251 के एक्यूआइ के साथ दर्ज है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर (एक्यूआइ 215), चौथे पायदान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका 211, एक्यूआइ के साथ है। भारत का कोलकाता भी 211 के एक्यूआइ के साथ पांचवें स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। राजधानी दिल्ली हांफ रही है, खांस रही है। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की जरूरत है। दिल्ली-एनसीआर इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश ही नहीं दुनिया भर के अखबारों-समाचार चैनलों, वेबसाइट्स में दिल्ली की हवा सुर्खियों में है। दिल्ली एनसीआर में इस समय धुंध नहीं बल्कि, हवा में मौजूद धूल के कारण है, वो धूल जो कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से कभी पोल्यूशन की वजह से कभी पराली की वजह से घटना हो रही है।

ये लटके हुए कण जो धूल के हैं ये पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे महीन कण इसमें शामिल हैं।

इसका मतलब यह है कि एक दिन की दिल्ली की हवा में सांस लेना करीब 50 सिगरेट के पीने के बराबर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हवा का क्या हाल है। रोज पीने-उपयोग करने वाला भूजल भी अब दिल्ली में सुरक्षित नहीं बचा है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड की नई रिपोर्ट बताती है कि इस पानी में यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्वों के साथ नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और ज्यादा नमक तक मिला हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी के कई हिस्सों से लिए गए भूजल के नमूनों में यूरेनियम की मात्रा सामान्य सीमा से कहीं अधिक पाई गई। यूरेनियम धीरे-धीरे शरीर में जमा होता है और गुर्दों, हड्डियों और शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है।

रिपोर्ट में साफ हुआ कि पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और ज्यादा नमक भी पाया गया है। नाइट्रेट ज्यादातर गंदे पानी और खाद से जमीन में रिसकर आता है। फ्लोराइड बढ़ने से दाँत और हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं। लेड शरीर के दिमागी विकास पर भारी असर डालता है और बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। नमक और घुले पदार्थ ज्यादा होने से पानी पीने लायक नहीं रह जाता और पाचन व गुर्दों पर दबाव पड़ता है। दिल्ली में लगातार ज्यादा गहराई तक बोरिंग होने लगी है, जिससे ऐसे हिस्सों का पानी ऊपर आ रहा है जहाँ मिट्टी में खुद ही खनिज और भारी तत्व मौजूद रहते हैं। दूसरी ओर, सीवर रिसाव, गंदे पानी का जमीन में घुसना और रासायनिक कचरे का सही निस्तारण न होना भी भूजल को जहरीला बना रहा है। जमीन रिचार्ज होने की जगह घट गई है और पानी अपना प्राकृतिक संतुलन खो रहा है। दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण भी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन रहा है।

दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और यमुना में झाग भी बनने लगते हैं। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में सफेद झाग दिखाई दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह झाग पानी में मौजूद फॉस्फेट, डिटर्जेंट और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण बनता है। यह न सिर्फ नदी के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। सवाल यही है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली वायु–जल प्रदूषण को लेकर और कितनी रसातल तक जाएगी। आखिर नेताओं और सरकारों की कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी। चुनी हुई सरकारों से उम्मीद की जाती है कि जनहित का ख्याल रखेंगी। इस लिहाज से दिल्ली किसी बुरे सपने से कम नहीं है।

डिजिटल हमलों से डरती महिलाएं

रवि जैन

दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल साधनों का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके महिलाओं को बदनाम करने, परेशान करने और ब्लैकमेल करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (यूएनओ) ने इस वर्ष 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक के 16 दिवसीय सक्रियता अभियान की थीम ही महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध डिजिटल हिंसा को समाप्त करने पर केंद्रित की है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए वातावरण तैयार करना है।

'यूएनओ' के अनुसार महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा हर तीन में से एक महिला को प्रभावित करती है। यह एक वैश्विक मानवाधिकार आपातकाल है जिसे रोका जाना चाहिए। दुर्व्यवहार के सबसे तेजी से बढ़ते रूपों में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध डिजिटल हिंसा प्रमुख है। भारत में जितनी तेजी से डिजिटल क्रांति हुई है, उतनी तेजी से कोई क्रांति नहीं हुई। डिजिटल क्रांति ने मोबाइल फोन और इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचा दिया है। इसकी बदौलत आम जनता में जागरूकता और सशक्तिकरण जहां सकारात्मक पक्ष है, वहीं इसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक नया रूप भी उभर कर सामने आया है। इसे ही 'डिजिटल हिंसा' नाम मिला है। यह वही हिंसा है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां सालों से वास्तविक दुनिया में करती रही हैं, पर डिजिटल युग में अब उसका रूप और माध्यम बदल गया है। 'यूएनओ' के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह द्वारा की गई वह हिंसा, जिसकी जड़ें लैंगिक असमानता या भेदभाव में हों और जिसमें डिजिटल या संचार तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो, उसे डिजिटल लिंग आधारित हिंसा कहा जाता है। 'यूएनओ' के 'जनसंख्या कोष' (यूएनएफपीए) के मुताबिक डिजिटल हिंसा महिलाओं और लड़कियों के लिए सामाजिक बदनामी का कारण बनती है। इस वजह से एक ओर उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहीं इस कारण वे ऑफलाइन और ऑनलाइन संसार में अलग-थलग पड़ जाती हैं। इसका परिणाम शैक्षणिक संस्थानों और नेतृत्व की भूमिकाओं में उनकी भागीदारी प्रभावित होने के रूप में भी निकल रहा है। महिलाओं के विरुद्ध 'डिजिटल हिंसा ऑनलाइन हैरॉसमेंट,' 'हेट स्पीच,' तस्वीरों से छेड़छाड़, ब्लैकमेल, भद्दे संदेश भेजने और अवांछित कॉल जैसे कई रूपों में सामने आ रही है। 'आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस' (एआई) के दौर में फर्जी वीडियो, 'डीपफेक' और एडिटेड कंटेंट तैयार करना पल भर का काम हो गया है। ऐसे में महिलाओं के लिए समस्या और भी बढ़ गई है।

महिलाएं किस कदर डिजिटल हिंसा को झेल रही हैं, इसका अनुमान 'द इकानॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' के एक सर्वे से लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक दुनिया में 85 प्रतिशत महिलाओं को किसी-न-किसी रूप में ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ा है।

भारत में स्थिति चिंताजनक है। 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (एनसीआरबी) के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के मामले तेजी से बढ़े हैं जिनमें ब्लैकमेलिंग, बदनाम करना, तस्वीरों से छेड़छाड़, अभद्र सामग्री भेजना और फेक प्रोफाइल बनाना जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। महिलाओं और लड़कियों का पीछा करने, उन्हें परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है। आज महिलाएं डिजिटल दुर्व्यवहार के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। कब कोई किसी महिला की अंतरंग तस्वीरों को बिना उसकी अनुमति के सोशल मीडिया पर डाल दे या कब कोई व्यक्ति किसी महिला की फर्जी या डिजिटल रूप से हेरफेर की गई न्यूड तस्वीर अथवा वीडियो बनाकर सार्वजनिक कर दे, कौन जानता है। इसके बाद ब्लैकमेलिंग, धमकाने और यौन उत्पीड़न का सिलसिला भी अब कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं रह गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा और भद्दे कमेंट्स अब रोजमर्रा की बात हो गई है। ये घटनाएं केवल ऑनलाइन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि कई

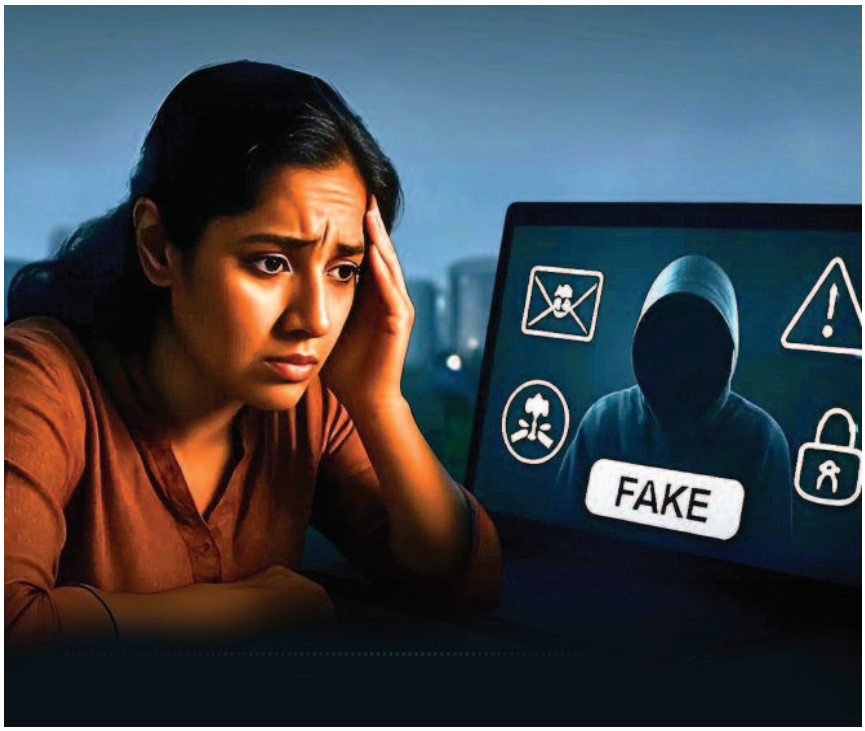

बार यही मानसिक और सामाजिक हिंसा, वास्तविक जीवन में शारीरिक शोषण और हत्या तक का कारण बन जाती है।

बड़ा सवाल है कि आखिर डिजिटल हिंसा क्यों बढ़ रही है? डिजिटल हिंसा का एक बड़ा कारण टेक्नालॉजी प्लेटफॉर्म के लिए कमजोर नियम और कानूनी ढांचे की अपर्याप्तता है। अधिकांश देशों में अब तक डिजिटल हिंसा को अलग अपराध के रूप में कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारत में भी कानून तो हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की जरूरत है। समस्या की एक बड़ी वजह सोशल नेटवर्किंग साइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही का अभाव भी है। ये प्लेटफॉर्म अक्सर महिलाओं के उत्पीड़न या निजी डाटा के दुरुपयोग पर समय पर कार्रवाई नहीं करते। ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग प्रक्रिया जटिल है और कई बार पीड़ित महिलाओं को उल्टा शर्मिंदगी और समाज के संदेह का सामना करना पड़ता है।

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल दुर्व्यवहार को रोकना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अपराधी अदृश्य, गुमनाम और तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं। वे नकली पहचान, वीपीएन या फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी पहचान छिपी रहती है। साथ ही, सोशल मीडिया का तेज प्रसार, डाटा का निजीकरण न होना और डिजिटल साक्षरता की कमी भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। हमारे यहां ज्यादातर महिलाओं को यह भी नहीं पता होता कि उनके पास क्या कानूनी अधिकार हैं और वह ऐसे मामलों में शिकायत कैसे दर्ज कराएं।

सवाल यह उठता है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल हिंसा को समाप्त करना किसी एक संस्था या सरकार का नहीं, बल्कि साझा प्रयासों का काम है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार को सख्त और स्पष्ट कानून बनाने होंगे। पुलिस और न्याय व्यवस्था में डिजिटल अपराधों की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। टेक्नालॉजी कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है। 'एआई' के दौर मे 'डीपफेक,' फेक प्रोफाइल और ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ स्वचालित सुरक्षा तंत्र विकसित किए बिना समाधान की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। समाज को भी रवैया बदलना होगा। पूर्वाग्रह के चलते ऐसे मामलों में महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि जरूरत इस बात की है कि पीड़ित महिलाओं को दोष देने के बजाय उनकी मदद की जाए। मीडिया को डिजिटल हिंसा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ानी होगी। अब समय आ गया है, जब स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल नैतिकता और ऑनलाइन सुरक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम जोड़ने चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजिटल युग में हिंसा का चेहरा बदल गया है, लेकिन उसका असर उतना ही गहरा है। डिजिटल हिंसा की शिकार हुई महिलाओं से इस बारे में पूछा जाए तो इसका पता चल सकता है।

सर्दियों में वेलवेट बॉर्डर साड़ी से पाएं एलीगेंट और स्टाइलिश लुक, दिखेंगी सबसे खास!

सर्दियों के फैशन में वेलवेट साड़ियों का बोलबाला है, जो आपको बेहद स्टनिंग लुक दे सकती हैं। यह लेख फ्लोरल, कटवर्क और जरी बॉर्डर वर्क वाली वेलवेट साड़ियों को चुनने और स्टाइल करने के आसान तरीके बताता है, जिससे आप किसी भी पार्टी या फंक्शन में एलीगेंट दिखेंगी। ये डिजाइनर साड़ियां विंटर ट्रेंड में अपनी जगह बना चुकी हैं।

हर भारतीय नारी की पहचान साड़ी है। साड़ी पहनना हम सभी को काफी पसंद है। ज्यादातर महिलाएं अलग-अलग फैब्रिक और डिजाइन वाली साड़ी खरीदते है। हालांकि, सर्दियों के मौसम में वेलवेट फैब्रिक वाली साड़ी बेहद खास होती है। विंटर सीजन में वेलवेट साड़ी काफी डिमांड में होती है। ऐसे में आप वेलवेट फैब्रिक की साड़ी खरीदकर उसे ट्रेंडी अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं। इस बार किसी खूबसूरत बॉर्डर वर्क वाली वेलवेट साड़ी को चुनें, जिससे आपका लुक अलग और आकर्षक दिखे। आइए, आर्टिकल में जानते हैं कि वेलवेट बॉर्डर वर्क वाली साड़ियों के कौन-कौन से स्टाइल आप पहन सकती हैं।

फ्लोरल वर्क वाली वेलवेट साड़ी

आप अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए फ्लोरल बॉर्डर वर्क वाली वेलवेट साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं। वेलवेट फैब्रिक पर किया गया फ्लोरल बॉर्डर वर्क साड़ी को हैवी और एलीगेंट लुक देता है। इसके साथ मिलने वाला सेम बॉर्डर वर्क वाला ब्लाउज पूरे आउटफिट को और भी खूबसूरत बनाता है। चाहें तो आप इस तरह की साड़ी को कॉन्ट्रास्ट रंग में चुनकर भी स्टाइल कर सकती हैं। इससे आपका लुक और ज्यादा निखरकर सामने आएगा।

कटवर्क बॉर्डर वर्क वेलवेट साड़ी

कटवर्क बॉर्डर वर्क साड़ी को स्टाइल करेंगी, तो इसमें आप बहुत प्यारी लगेंगी। यह साड़ी ज्यादा हैवी नजर नहीं आती है। वेलवेट साड़ी को आप आसानी से वियर कर सकते हैं। इस साड़ी के साथ आपको हैवी वर्क में ब्लाउज डिजाइन मिलेगा। इस तरह की साड़ी को किसी भी पार्टी या फंक्शन में वियर कर सकती है।

जरी वर्क बॉर्डर वाली वेलवेट साड़ी

किसी फंक्शन या पार्टी में सुंदर दिखने के लिए आप जरी वर्क बॉर्डर वाली वेलवेट साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं। वेलवेट साड़ी पहनने के बाद अच्छी लगेगी। इससे आपकी साड़ी का लुक भी अच्छा नजर आएगा। इसके साथ ही साड़ी का कलर भी बैलेंस हो जाएगा। इस तरह की साड़ी आपको मार्केट मिल जाएगी।

विंटर में मॉइश्चराइजर व क्रीम लगाना है फायदेमंद

इस मौसम में ठंडी हवाएं त्वचा की नमी छीन लेती है। यही कारण है कि हमारी स्किन ड्राई, बेजान और फटी-फटी सी लगती है। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मॉइश्चराइजर या क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन विंटर में ड्राई स्किन के लिए दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है?

ह सर्दियो के मौसम में सबसे ज्यादा ड्राई स्किन की समस्या परेशान करती है। इस मौसम में ठंडी हवाएं त्वचा की नमी छीन लेती है। यही कारण है कि हमारी स्किन ड्राई, बेजान और फटी-फटी सी लगती है। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मॉइश्चराइजर या क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन विंटर में ड्राई स्किन के लिए दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है? आप भी कन्फ्यूज है तो जानिए सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए मॉइश्चराइजर लगाएं या क्रीम।

मॉइश्चराइजर क्या करता है?

मॉइश्चराइजर रोजाना इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होता है। यह त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है और उसकी नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। इसे दिन में किसी भी समय लगाया जा सकता है। मेकअप करने से पहले लगाने पर भी यह त्वचा को स्मूद बनाता है। आमतौर पर मॉइश्चराइजर में ग्लिसरीन, हायलूरोनिक एसिड और एलोवेरा जैसे तत्व होते हैं, जो स्किन की नमी को लॉक करके उसे मुलायम और स्वस्थ रखते हैं।

किसके लिए सही है?

- ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है।
- ऑफिस जाने वालों के लिए।
- उन जगहों पर जहां कड़ाके की ठंड नहीं होती है।

क्रीम क्या करती है?

क्रीम मॉइश्चराइजर से ज्यादा ही हैवी होती है। यह स्किन पर एक मोटी लेयर बनाती है। इसके साथ ही नमी को लंबे समय तक के लिए लॉक करती है। यदि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर फटी-फटी सी महसूस होती है, तो क्रीम बेस्ट ऑप्शन है। क्रीम स्किन को शुष्क हवाओं से बचाने में मदद करती है।

किसके लिए सही है?

- जिन लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई या खुजली वाली स्किन है।
- रात में सोने से पहले
- जिनकी स्किन ठंड में जल्दी फटने लगती है।

मॉइश्चराइजर या क्रीम लगाएं?

यदि आपकी स्किन कम ड्राई है तो मॉइश्चराजर सही रहेगा। यदि स्किन ज्यादा ही ड्राई, खिंची-खिंची और और खुजली वाली है, यह लोग क्रीम लगाएं। दिन में लाइट प्रोडक्ट और रात में थोड़ा भारी प्रोडक्ट लगाया जाता है।

कैसे इस्तेमाल करें

- सबसे पहले आप चेहरे को धोने के दो मिनट के अंदर मॉइश्चराइजर या क्रीम लगाएं।
- सर्दियों में ज्यादा ही गर्म पानी से स्नान न करें।
- दिन में दो बार स्किन जरुर मॉइश्चराइज करें।

नव्य, दिव्य और अलौकिक अयोध्या तीव्र गति से हो रहा सर्वांगीण विकास

अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अनेक परियोजनाएं हो रहीं संचालित

दिव्य एवं भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में अयोध्या का कायाकल्प अभूतपूर्व गति से हो रहा है। अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अनेक परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र ने शहर के आर्थिक

अरुण मिश्रा

विकास को नई रफ्तार दी है। नए उद्योगों और व्यवसायों के स्थापित होने से रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं।

अयोध्या में विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है। हनुमानगढ़ी से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक भक्ति पथ का निर्माण पूरा हो चुका है। सुगम्य अयोध्या के तहत महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का निर्माण भी पूर्ण हो गया है। सहादतगंज से नयाघाट तक लगभग 13 किलोमीटर लंबी चार लेन सड़क

का निर्माण तथा अयोध्या-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 330 और लता मंगेशकर चौक से गोरखपुर राजमार्ग तक धर्मपथ का चार लेन विस्तार पूरा हो चुका है।

श्रीराम मंदिर निर्माण के उपरांत अयोध्या में श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, गरुण और जटायू नामक छह भव्य प्रवेश द्वार विकसित किए गए हैं। अयोध्या के 11 ब्लॉकों में मियावाकी पद्धति के माध्यम से 55 वैदिक वनों का विकास किया गया है। 'नव्य अयोध्या' के अंतर्गत हरित क्षेत्र विस्तार और हाईटेक वेलनेस सिटी के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। लगभग ₹750 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें ₹650 करोड़ भवन निर्माण पर तथा ₹100 करोड़ आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना टाटा संस द्वारा उरफपहल के तहत वित्तपोषित की जा रही है। यह संग्रहालय देश की प्रमुख वैष्णव परंपराओं, उनकी मंदिर वास्तुकला, इतिहास और परंपराओं का भव्य प्रतिनिधित्व करेगा।

अयोध्या में आवास विकास परिषद द्वारा 550 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जा रही है, जिसे 'नव्य अयोध्या' योजना का प्रमुख घटक माना जा रहा है। यह प्रदेश की सर्वाधिक हाईटेक टाउनशिप में से एक होगी। लगभग ₹218 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और इलेक्ट्रिक डक्ट का निर्माण हो रहा है। करीब 200 एकड़ क्षेत्र को हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा। टाउनशिप में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल जोन और हाईटेक प्रौद्योगिकी पार्क के लिए भी भूखंड तैयार किए जा रहे हैं, जो 'वेलनेस सिटी' की अवधारणा को मजबूती प्रदान करते हैं।

अयोध्या में ₹750 करोड़ की लागत से म्यूजियम ऑफ टेंपल्स का निर्माण प्रगति पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान अयोध्या के लिए 159 एमओयू सम्पन्न हुए हैं। शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। करोड़ों के निवेश के साथ 5-सितारा और 4-सितारा श्रेणी की लगभग 42 होटल श्रृंखलाएं विकसित हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी घोषित किया गया है। सरयू नदी के तट पर माझा रामपुर हलवारा और माझा सरायरासी गांवों में 40 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। लगभग 165 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराई गई है। यह संयंत्र अयोध्या की अनुमानित 198 मेगावाट विद्युत आवश्यकता के 10% के बराबर 40 मेगावाट उत्पादन कर रहा है, जो वर्तमान जरूरतों का लगभग 25-30% पूरा करता है।

दिव्य अयोध्या और मेटावर्स पहल

'अयोध्या यात्रा' ऐप लॉन्च किया गया है, जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से श्रीराम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू घाट का 360-डिग्री वर्चुअल दर्शन संभव है। भक्त घर बैठे पूजा भी करवा सकते हैं। ऐप में मेटावर्स तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिससे दीपोत्सव जैसे आयोजनों का 3D वर्चुअल अनुभव प्राप्त किया जा सकता है।

मियावाकी वैदिक वन

मियावाकी पद्धति से जिले के सभी 11 ब्लॉकों में पाँच-पाँच स्थलों पर कुल 55 वैदिक वन बनाए गए हैं। पौधों की सुरक्षा हेतु GPS टैगिंग की गई है तथा रखरखाव और सिंचाई का कार्य मनरेगा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।

भारत की पारंपरिक चिकित्सा की रोशनी में विश्व-स्वास्थ्य

आज की दुनिया गहन और बहुआयामी स्वास्थ्य संकटों से गुजर रही है। एक ओर जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ, मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और असंतुलन तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर संक्रामक रोग, महामारी और पर्यावरणीय विषमताएँ मानव जीवन को निरंतर चुनौती दे रही हैं। इन परिस्थितियों के बीच यह स्पष्ट होता जा रहा है कि केवल आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा के सहारे वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं का संपूर्ण समाधान संभव नहीं है। यही कारण है कि विश्व समुदाय का ध्यान पुनः भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की ओर आकर्षित हो रहा है, जिनमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पद्धतियाँ शामिल हैं। जिन्हें 'आयुष' के नाम से जाना जाता है; ये प्रणालियाँ समग्र स्वास्थ्य, प्राकृतिक उपचार और शरीर-मन संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिनमें आयुर्वेद सबसे प्राचीन और

डॉ. निमित त्यागी

सुव्यवस्थित प्रणालियों में से एक है, जो अपने दार्शनिक आधार और विविध उपचार विधियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चिकित्सा प्रणालियों का आधार केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा है।

आयुर्वेद शरीर के तीन दोषों (वात, पित्त, कफ) के संतुलन पर केंद्रित; आहार, जीवनशैली, जड़ी-बूटी और पंचकर्म (शुद्धिकरण) जैसी तकनीकों का उपयोग करती है। अष्टांग आयुर्वेद अर्थात कायचिकित्सा (आंतरिक चिकित्सा), शल्य (सर्जरी), कौमारभृत्य (बाल चिकित्सा), भूतविद्या (मनोविज्ञान), अगद तंत्र (विष विज्ञान), रसायन (जराचिकित्सा), वाजीकरण (प्रजनन) और शालक्य (नेत्र/कान/नाक) में विभाजित है। आयुर्वेद की ही भांति योग भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जो शारीरिक आसन (आसन), प्राणायाम (सांस लेने के व्यायाम), ध्यान (मेडिटेशन) और नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से मन-शरीर के समन्वय पर केंद्रित है। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी, पानी, धूप और आहार जैसी प्राकृतिक तरीकों से शरीर की स्व-उपचार क्षमता को बढ़ावा देती है। यूनानी चिकित्सा प्रणाली भी भारत में प्रचलित है, यूनान से आई यह प्रणाली शरीर के चार हमर (रक्त, बलगम, पीला पित्त, काला पित्त) के संतुलन पर जोर देती है और पर्यावरण के प्रभाव को मानती है। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित है, जिसमें जड़ी-बूटियों और धातुओं से बनी दवाओं का उपयोग और योग व ध्यान पर जोर दिया जाता है।

सोवा-रिग्पा पहाड़ों की चिकित्सा प्रणाली है, हिमालयी क्षेत्रों (जैसे लद्दाख, सिक्किम) में प्रचलित है, जिसे 'तिब्बती चिकित्सा' के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से इन प्रणालियों के विकास, अनुसंधान और मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकरण को बढ़ावा देता है। ये प्रणालियाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित हैं और अब वैश्विक स्वास्थ्य मंच पर भी अपनी पहचान बना रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इन पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने इसे केवल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की एक प्रभावी, सुलभ और टिकाऊ स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ पारंपरिक चिकित्सा को लेकर साझेदारी और वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन इस दिशा में ठोस कदम हैं। हाल ही में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि भारत अब इस क्षेत्र में केवल सहभागी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात में हुई वृद्धि इस परिवर्तनशील परिदृश्य को स्पष्ट रूप से दशार्ती है। 61.1 मिलियन डॉलर से बढ़कर 65.1 मिलियन डॉलर तक पहुँचना केवल आर्थिक आँकड़ा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक विश्वास का संकेत है। दुनिया के अनेक देश यह समझने लगे हैं कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ न केवल सस्ती और सुलभ हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती हैं। यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब विश्व की लगभग एक चौथाई आबादी आर्थिक कारणों से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में पारंपरिक चिकित्सा एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में उभरती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज भी दुनिया के लगभग 170 देशों में 40 से 90 प्रतिशत आबादी किसी-न-किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। यह आँकड़ा इस धारणा को तोड़ता है कि पारंपरिक चिकित्सा केवल विकासशील देशों तक सीमित है। वास्तव में विकसित देशों में भी योग, आयुर्वेदिक उपचार, हर्बल औषधियाँ और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण आधुनिक चिकित्सा से जुड़े दुष्प्रभाव, अत्यधिक दवाओं पर निर्भरता और महँगी उपचार प्रक्रियाएँ हैं। एलोपैथिक चिकित्सा ने जहाँ त्वरित राहत और शल्य चिकित्सा में अद्भुत प्रगति की है, वहीं इसके साथ दवाओं के साइड इफेक्ट, एंटीबायोटिक प्रतिरोध और दीर्घकालिक जटिलताएँ भी जुड़ी हैं। इसके विपरीत भारतीय पारंपरिक चिकित्सा रोग की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करती है। आयुर्वेद शरीर की प्रकृति, दोषों के संतुलन और जीवनशैली के सुधार पर बल देता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मिक संतुलन का मार्ग है। इन पद्धतियों का उद्देश्य रोग को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक उपचार क्षमता को जाग्रत करना है। यही कारण है कि इन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित, कम दुष्प्रभाव वाली और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है।

पारंपरिक चिकित्सा के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत ने इस दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखा। ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, मेक्सिको, नेपाल, श्रीलंका सहित 16 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा अब कूटनीति और वैश्विक सहयोग का भी एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया 'आयुष मार्क' एक ऐतिहासिक पहल है, जो आयुष उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता का वैश्विक मानक स्थापित करेगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता भी मजबूत होगी। हालाँकि यह भी सत्य है कि पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, वैज्ञानिक शोध और प्रमाणिकता के प्रश्न लंबे समय से उठते रहे हैं। कई बार अप्रमाणित दावे और मिलावटी उत्पाद इस पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देते हैं। किंतु 'आयुष मार्क' जैसी पहलों और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बनाया जाए, ताकि दोनों की श्रेष्ठताओं का समन्वय हो सके।

मानव-मन की अदृश्य दरारें दर्शाता 'धुरंधर'

फिल्म का सबसे बड़ा जोखिम उसका 214 मिनट का रनटाइम है। यह धैर्य मांगती है, और सामान्य दर्शक के लिए यह चुनौती है। कुछ सबप्लॉट्स, विशेषकर दूसरे हिस्से में, कहानी को भारपूर्ण बनाते हैं। कुछ दर्शकों को यह फिल्म अपने राजनीतिक स्वर में अत्यधिक स्पष्ट और कभी-कभी जिद्दी भी प्रतीत हो सकती है।

आज के सिने-सोहबत में एक ऐसी फिल्म पर बात करते हैं, जिसके इर्द-गिर्द देश भर में चर्चा छिड़ गई है। फिल्म का नाम है 'धुरंधर'। इसके निर्देशक आदित्य धर हैं, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म 'उरी' से ये सिद्ध कर दिया था कि हिंदी सिनेमा उद्योग में एक धुरंधर फि ल्मकार का आगमन हो चुका है।

भारतीय सिनेमा में जासूसी आधारित फिल्मों की अपनी सीमाएं और अपनी विरासत रही है। कभी अत्यधिक स्टाइलाइज्ड, कभी अत्यधिक राष्ट्रवादी, और कभी-कभी केवल बाहरी रोमांच तक सीमित। ऐसे परिदृश्य में, आदित्य धर की 'धुरंधर' एक असामान्य हस्तक्षेप की तरह उभरती है। एक ऐसी फि ल्म जो जासूसी की राजनीतिक, भावनात्मक और वैचारिक परतों को एक साथ पकड़ने का प्रयत्न करती है। लगभग 214 मिनट लंबी यह फि ल्म केवल एक मनोरंजक थ्रिलर नहीं, बल्कि भारतीय खुफिया व्यवस्था, सीमा-पार तनाव और वैयक्तिक नैतिकता के अंतसंबंधों पर एक व्यापक सिनेमाई टिप्पणी भी है।

इस फि ल्म की मूल संरचना जासूसी, अपराध और राजनीतिक रणनीति के त्रिकोण से निर्मित है। लेकिन इसका वास्तविक आकर्षण इसकी आंतरिक बेचैनी, उसके किरदारों के नैतिक द्वंद्व, और उसके भीतर छिपे हुए नैरेटिव माइंड-गेम्स हैं। 'धुरंधर' की कहानी कई भूगोलों, कई एजेंसियों और कई व्यक्तिगत एजेंडों के बीच फैलती है। यह वही विस्तार है जो फि ल्म को विशिष्ट भी बनाता है और चुनौतीपूर्ण भी। भारत की खुफिया एजेंसी के भीतर कार्यरत एक एजेंट (रणवीर सिंह), एक जटिल अंडरवर्ल्ड नेटवर्क, पाकिस्तान की राजनीतिक-अपराधिक गठजोड़ और दक्षिण एशियाई सुरक्षा प्रतिद्वंद्विता, ये सभी मिलकर फि ल्म की वैचारिक रीढ़ तैयार करते हैं। जासूसी फिल्मों में अक्सर राष्ट्र एक रोमांटिक प्रतीक बनकर उभरता है, पर 'धुरंधर' राष्ट्र को एक नैतिक इकाई की बजाय एक रणनीतिक मशीन के रूप में देखता है। यह दृष्टि फि ल्म को परिपक्वता देती है। आदित्य धर यहां यह प्रश्न उठाते प्रतीत होते हैं कि 'क्या एक एजेंट की वफादारी केवल राष्ट्र की होती है, या उसके अपने अनुभव, उसके अपने घाव और उसके अपने सत्य भी उसकी वफादारी को आकार देते हैं'?

'धुरंधर' की खास बात ये कि इस फिल्म में राष्ट्रवाद केवल नारा नहीं, बल्कि संघर्ष का विषय है। फि ल्म का सबसे बड़ी बौद्धिक संपत्ति उसका किरदार-लेखन है। जासूस, अपराधी, राजनेता, सबके भीतर एक अदृश्य दरार है, जिसे फिल्म बहुत धैर्य से उजागर करती है।

रणवीर सिंह का एजेंट वाला चरित्र अपनी ऊर्जा और हिंसक सटीकता के कारण रोचक तो है, पर वास्तविक गहराई उसे उसके आंतरिक खोखलेपन से मिलती है। वह सिर्फ एक मिशन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अनसुलझा, आधा टूटा हुआ मनुष्य है जो दुश्मनों से कम और अपने विवेक से अधिक लड़ता है। एक दृश्य में उसकी चुप्पी, कैमरे का उसके चेहरे पर ठहरना, और पीछे चलती हल्की थरथराती सांसें साफतौर पर यह दिखाती हैं कि जासूसी काम सिर्फ राष्ट्र-रक्षक का आवरण नहीं, बल्कि लगातार आत्म-क्षय का अनुभव भी है।

अक्षय खन्ना का चरित्र फि ल्म की सबसे सूक्ष्म उपलब्धियों में से है। यहां खलनायकी शोर या अति-नाटकीयता में नहीं, बल्कि बौद्धिक ठंडक में स्थित है। उनकी निगाहें, उनकी धीमी आवाज, और उनका तिरछा सत्य, सब मिलकर यह दशार्ते हैं कि आतंक और अपराध कभी-कभी वक्तृता की बजाय दार्शनिकता से भी जन्म ले सकते हैं।

अन्य कलाकारों की बात करें तो आर माधवन और संजय दत्त जैसे कलाकार कथा में एक परिपक्वता और स्थायित्व जोड़ते हैं। उनके किरदार भारत-पाक राजनीति के बीच मौजूद भूरे क्षेत्रों की तरह हैं, न पूरी तरह नैतिक, न पूरी तरह अलोकतांत्रिक। ताउम्र कॉमेडी से अपनी पहचान बनाने वाले कलाकार राकेश बेदी का काम इस फिल्म में इतना शानदार है कि ये किरदार उनकी अभिनय यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होने में कोई कसर नहीं छोड़ता है।

कहानी और परफॉर्मन्स के अलावा 'धुरंधर' अपने सिनेमाई डिजाइन और प्रभाव के लिए भी देखी जानी चाहिए। आदित्य धर पहले से ही बड़े पैमाने के अनुभवों के निर्देशक रहे हैं, पर 'धुरंधर' में वे अपने सिनेमाई दृष्टिकोण को और अधिक विस्तृत करते हैं। इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो यहां कैमरा सिर्फ दृश्य नहीं पकड़ता, बल्कि यह मनोविज्ञान पकड़ता है। क्लोज-अप्स में एक अजीब-सी शांति है, और वाइड शॉट्स में एक गहरी बेचैनी। शहरों की सांस, सीमाओं की खामोशी, अंधेरों की किरकिराहट, सब दृश्यात्मक रूप से कहानी की भाषा बन जाते हैं।

'धुरंधर' की एक्शन कोरियोग्राफी भी लाजवाब है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस 'स्पेक्टेकल' होने के साथ-साथ 'नैरेटिव' भी हैं। हर गोली, हर धमाका, हर पीछा, किरदारों के निर्णय, डर और आत्मधारणा का विस्तार है। यहां हिंसा अर्थहीन नहीं, बल्कि कहानी का दार्शनिक तनाव है।

फिल्म का संगीत, साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर कहानी को सिर्फ सहयोग नहीं करता बल्कि इसे व्याख्यायित भी करता है। ऊंचे सुरों और खामोशी के बीच लगातार होता उतार-चढ़ाव फिल्म के भाव-परिदृश्य को और भी जटिल बनाता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा जोखिम उसका 214 मिनट का रनटाइम है। यह धैर्य मांगती है, और सामान्य दर्शक के लिए यह चुनौती है। कुछ सबप्लॉट्स, विशेषकर दूसरे हिस्से में, कहानी को भारपूर्ण बनाते हैं। कुछ दर्शकों को यह फिल्म अपने राजनीतिक स्वर में अत्यधिक स्पष्ट और कभी-कभी जिद्दी भी प्रतीत हो सकती है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि यह फिल्म धीमी नहीं, बल्कि विस्तृत है। यह एक ऐसी कथा है जिसे निर्देशक ने त्वरित मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव के लिए रचा है।

इस फिल्म के कथ्य की बात करें तो इसकी थीमेटिक गहराइयां भी बहुत कुछ कहती है। इस फिल्म में राष्ट्र और व्यक्ति का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। ये फिल्म यह प्रश्न निरंतर उठाती रहती है कि 'क्या राष्ट्र-हित हमेशा व्यक्ति-हित से ऊपर होता है' ? और यदि हां, तो उस व्यक्ति का भावनात्मक मुआवजा कौन देगा ? फिल्म में हिंसा की दार्शनिकता भी है है। यहां हिंसा सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि निर्णयों में भी है। किसे बचाना है ? किसे छोड़ना है ? किसे मारना आवश्यक है और क्यों ? 'धुरंधर' के लेखन में राजनीति की अदृश्य मशीनरी पर भी काफी सूक्ष्म है। फिल्म दिखाती है कि राजनीति और खुफिया दुनिया में नायक और खलनायक स्थिर पहचानें नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों से निर्मित, टूटती-बनती भूमिकाएं हैं।

कई मायनों में 'धुरंधर' एक महत्वपूर्ण फिल्म है और इस पर जितनी चर्चा की जाए, कम है। 'धुरंधर' भारतीय सिनेमा में एक दुर्लभ उदाहरण है। एक ऐसी फिल्म जो मनोरंजन और बौद्धिकता के बीच पुल बनाती है। यह दर्शकों को केवल रोमांचित नहीं करती, बल्कि उन्हें सोचने, विचारने, और कई मामलों में असहज होने के लिए भी मजबूर करती है।

यह फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जासूसी और राजनीति को सिर्फ नारा नहीं, बल्कि अध्ययन का विषय बनाती है। यह दिखाती है कि राष्ट्रवाद और मानवता हमेशा सरल समीकरण नहीं होते और सबसे महत्त्वपूर्ण बात कि 'धुरंधर' यह दशार्ती है कि जासूस भी मनुष्य होते हैं, दुःख, स्मृति और पछतावों से बने हुए मनुष्य।

'धुरंधर' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक वैचारिक बहस है जो हमें अपने समय, अपनी राजनीति और अपने नैतिक निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है।

हार्दिक पांड्या ने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा, अपने नाम किया ये रिकॉर्ड

महमूद रजा
बिजनौर

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज के पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मैच और सीरीज में जीत दिलायी। मैच में बल्ले के साथ ही गेंद से अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत हार्दिक पांड्या ने युवराज सिंह का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया।

हार्दिक पांड्या अहमदाबाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर टूट पड़े। हार्दिक सिर्फ बाउंड्री में ही बातें कर रहे थे। हार्दिक ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया। भारत की तरफ से टी20 में यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। पांड्या ने 25 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 63 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 के विशाल स्कोर तक पहुंच सकी।

हार्दिक ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 1 विकेट झटके

अंतरराष्ट्रीय टी20 में यह चौथा मौका था जब हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक लगाने के साथ ही 1 या उससे अधिक विकेट लिए। इस मामले में उन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा। युवराज ने टी20 में तीन बार फिफ्टी लगाने के साथ ही 1 या उससे अधिक विकेट लिए थे। विराट कोहली और शिवम दुबे भी 2-2 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

हार्दिक पांड्या को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैच का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। हार्दिक ने सीरीज का दूसरा अर्धशतक लगाया। सीरीज के पहले मैच में भी हार्दिक ने 28 गेंद पर नाबाद 59 रन बनाने के साथ ही 1 विकेट लिए थे।

पांचवें टी20 की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने तिलक वर्मा के 73, हार्दिक पांड्या के 63, सैमसन के 37, और अभिषेक शर्मा के 34 रन की बदौलत 8 विकेट पर 231 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बना सकी और मैच 30 रन से हार गई। क्विंटन डि कॉक ने सर्वाधिक 65 रन बनाए थे। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।

शुभमन गिल टी-20 विश्व कप 2026 से क्यों हुए बाहर

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा बीसीसीआई के सचिव देवजित सैकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। शुभमन गिल को भारतीय टीम में जगह नहीं दी गई है।

शुभमन गिल टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं। एशिया कप 2025 से पहले उन्हें टी20 फॉर्मेट का भी उपकप्तान बना दिया गया था। माना जा रहा था कि गिल को देर-सबेर टी20 फॉर्मेट की कप्तानी भी सौंप दी जाएगी, लेकिन गिल ने छोटे फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन से लगातार निराश किया है। इसी वजह से बीसीसीआई ने विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में रिस्क लेना उचित नहीं समझा और उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। गिल की जगह एक बार फिर अक्षर पटेल को उपकप्तान बना दिया गया है।

वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले गिल टी20 फॉर्मेट में प्रभावहीन रहे। एक, दो या तीन नहीं, बल्कि गिल लगातार 15 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। पिछली 15 पारियों में गिल ने 24.25 की साधारण औसत से मात्र 291 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है। गिल को भरपूर मौके मिले, लेकिन वे मौकों का फायदा उठाने में असफल रहे। इस वजह से विश्व कप जैसे बड़े इवेंट से उन्हें बाहर होना पड़ा।

2023 में टी20 फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले गिल ने 36 मैचों की 36 पारियों में 28.03 की औसत और 138.60 की स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं।

बतौर ओपनर संजू सैमसन ने पिछले कुछ समय से गिल से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी वजह से विश्व कप में गिल पर उन्हें प्राथमिकता दी गई है। सैमसन ने 52 टी20 मैचों की 44 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 1,032 रन बनाए हैं। संजू के तीनों शतक बतौर ओपनर आए हैं। बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ उनकी जोड़ी प्रभावी रही है।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह।

CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
VCB PANEL, CRP, TRANSFORMER, RMU ETC

SECURE METERS LTD.
ENERGY METER (POSTPAID/PREPAID/ SOLAR/ABT)

SECURE

MITSUBISHI ELECTRIC
MCB/MCCB/ACB/ CONTRACTOR/DB

MITSUBISHI ELECTRIC

Kumar Enterprises

GF-150 | DURGA TOWER | RDC | RAJ NAGAR | GHAZIABAD (UP) - 201001
TEL. : 0120-4137613 | EMAIL : ke.ghaziabad@gmail.com
SANJEEV KUMAR 9268566079

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

Assuring Excellence in Bath Faucets

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

खुशहाल किसान
उत्तर प्रदेश की पहचान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत
2.88 करोड़+ किसानों को ₹94,669 करोड़ हस्तांतरित

गन्ना किसानों को रिकॉर्ड
₹2.90 लाख करोड़ का भुगतान, मूल्य ₹315 से बढ़ाकर ₹400 प्रति क्विंटल

15 लाख+ किसान लाभान्वित
ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए उपयोग होने वाली बिजली के बिल माफ

गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू एवं शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP